वर्ष-10, अंक-9, जून-2025

मूल्य: ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

ईरान-इजरायल युद्ध

दुनिया के सामने नई चुनौती

खुशियों का उजाला

सौभाग्य
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना से

1.58 करोड़

घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन

हर घर रौशन

- 1,320 मेगावाट की जवाहरपुर, 660 मेगावाट की घाटमपुर, 660 मेगावाट की पनकी, 1,320 मेगावाट की ओबरा-सी एवं 1,320 मेगावाट की खुर्जा तापीय परियोजना का संचालन
- जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति
- 33/11 केवी के 42 नए विद्युत उपकेंद्र संचालित, 72 उपकेंद्रों का निर्माण, 1,081 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि
- किसानों के निजी नलकूप से सिंचाई के लिए बिजली के बिल पर शत-प्रतिशत छूट
- रूफटॉप सोलर पावर प्लांट : 400 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2,50,170 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना
- बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत 4000 मेगावाट क्षमता का प्लांट
- 53 कम्प्रेस्ड बायोगैस/बायो कोल/बायो डीजल एवं बायो इथेनॉल प्लांट की स्थापना

काम दमदार - डबल इंजन सरकार

अन्दर के पेजों में...

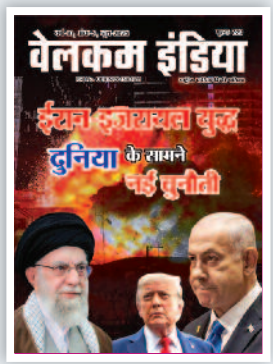

वर्ष- 10 अंक- 9

जून-2025

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

कवर स्टोरी
पेज-28

धर्म का एक दशक : मोदी युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण — पेज 03

अहमदाबाद विमान दुर्घटना दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण — पेज 06

दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'कैशलेस' उपचार: नीयत नेक, व्यवस्था बेकार — पेज 14

भारतीय संसदीय इतिहास के काले अध्याय के 50 साल — पेज 18

श्रेया घोषाल: विभिन्न भाषाओं में 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ भारत की नंबर 1 गायिका — पेज 52

IPL को मिला नया चैम्पियन कोहली के नाम रही 'विराट' विजय — पेज 54

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

इजराइल-ईरान युद्ध में क्या रहा हासिल?

ललित कुमार
सम्पादक

इजराइल-ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के कूदने से दुनिया के सामने विकट स्थितियां पैदा हो गई हैं। ईरान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर अमेरिका ने इस जंग में दखल दिया, तो न केवल उसको, बल्कि पूरी दुनिया को इसके खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी कह दिया था कि वे लाल सागर में हमले तेज कर देंगे। शुरू में अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह यह युद्ध रुक जाए, पर अब उसने खुद इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया है। उसने अपने बंकरभेदी बमवर्षकों से ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। इससे ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं। यह युद्ध क्या शक्ल अख्तियार करेगा, यह देखने की बात है। पर ईरान ने तत्काल होर्मुज जलडमरुमध्य को बंद करने का फैसला किया है, उसी से दुनिया के अनेक देशों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस जलडमरुमध्य के रास्ते दुनिया के करीब तीस फीसद कच्चे तेल का आयात होता है। जाहिर है, यह रास्ता बंद हो जाने से तेल के जहाजों को दूसरे लंबे रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसका असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ेगा। इससे महंगाई और बढ़ जाएगी।

ईरान के इस फैसले से भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि यह अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब सत्तर फीसद तेल आयात करता है। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरुमध्य के रास्ते पश्चिम एशियाई देशों के साथ बड़ी मात्रा में इसका आयात-निर्यात होता है। इन देशों के साथ भारत का निर्यात कुल 8.6 अरब डालर का और आयात 33.1 अरब डालर का होता है। इस रास्ते के बंद होने से इस व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले के चलते भारतीय व्यापारियों को पहले ही आयात-निर्यात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अमेरिकी हमले के विरोध में हूती हमलों में तेजी आई, तो यह संकट और गहरा हो जाएगा। भारत पहले ही अपना निर्यात बढ़ाने को लेकर चिंतित है। तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई पर काबू पाना चुनौती है। विनिर्माण क्षेत्र और देश के आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मंदी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और मध्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में अवरोध पैदा होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंच सकती है।

अमेरिकी हमले के बाद अभी दुनिया दम साधे इंतजार कर रही है कि ईरान इसका जवाब किस रूप में देता है। ईरान किसी भी रूप में झुकने को तैयार नहीं है। रूस सहित दुनिया के कई देशों ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। खुद अमेरिका में इसे लेकर विरोध शुरू हो गया है, इसलिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले में तय प्रक्रिया और नियम-कायदों का पालन नहीं किया। फिर यह भी कि अमेरिका या इजराइल के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में था।

अमेरिका की खुफिया एजंसी ने भी साफ कह दिया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। इस स्थिति में अगर कुछ देश ईरान के समर्थन में खुले रूप में आगे आते हैं, तो युद्ध और विकराल रूप ले सकता है। वैसी स्थिति में दुनिया के सामने खड़ी होने वाली आर्थिक चुनौतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

ईरान के इस फैसले से भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि यह अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब सत्तर फीसद तेल आयात करता है। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरुमध्य के रास्ते पश्चिम एशियाई देशों के साथ बड़ी मात्रा में इसका आयात-निर्यात होता है। इन देशों के साथ भारत का निर्यात कुल 8.6 अरब डालर का और आयात 33.1 अरब डालर का होता है। इस रास्ते के बंद होने से इस व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

धर्म का एक दशक

मोदी युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण

संजीव कुमार

जनवरी 2024 में, जब पावन नगरी अयोध्या में सूर्योदय हुआ। सदियों से लुप्त हो चुकी प्रार्थना अब आखिरकार गुंजायमान होने लगी थी। श्री राम की अपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महज एक धार्मिक उपलब्धि नहीं थी। यह सभ्यता के उद्धार का क्षण था। सदियों के आक्रमण, औपनिवेशिक विकृति और राजनीतिक देरी के बाद, मंत्रों से गूंजता हुआ और इतिहास के स्पंदन सहित, बलुआ पत्थर में उकेरा गया यह मंदिर शान से खड़ा था। यह सिर्फ वास्तुकला के बारे में नहीं था, यह एक घायल आत्मा के उपचार के बारे में था। श्री राम की अपनी जन्मभूमि पर वापसी ने उस राष्ट्र की आस्था को फिर से जागृत कर दिया, जिसने लंबे समय तक अपने दिल में निर्वासन की खामोशी को समेटे रखा था।

कुछ महीने पहले, भारत की प्राचीन आस्था का एक और प्रतीक चुपचाप अपने सही स्थान पर लौट आया। नई संसद के उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया। यह एक पवित्र राजदंड है, जिसे 1947 में तमिल अधीनमों ने सत्ता के धार्मिक हस्तांतरण को चिह्नित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया था। दशकों से,

इसे भुला दिया गया था, समुचित स्थान से वंचित किया गया, और एक प्रचलित राजदंड के तौर पर खारिज कर दिया गया था। इसकी स्थापना केवल स्मरण का कार्य नहीं था - यह एक शक्तिशाली घोषणा थी कि भारत अब खुद को उधार की आंखों से नहीं देखेगा। सेंगोल ने साम्राज्य के अवशेषों का नहीं, बल्कि धार्मिकता पर आधारित शासन का प्रतिनिधित्व किया। यह भारत की अपनी राज्य कला और आध्यात्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण आलिंगन था, जिसे उपनिवेशवाद के बाद के क्रम में लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था।

इतना ही नहीं, इन क्षणों ने एक गहरे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकेत दिया। यह एक सभ्यतागत गतिविधि के तौर पर ग्यारह परिवर्तनकारी वर्षों में सामने आएगी। 2014 में शुरू से ही यह स्पष्ट था कि मोदी सरकार के तहत संस्कृति अब सजावटी नहीं रहेगी, बल्कि यह मूलभूत होगी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। अब दुनिया भर में लाखों लोगों को एक प्राचीन भारतीय परंपरा का जश्न मनाते देखा जा रहा है, जो शरीर, मन और आत्मा को आपस में जोड़ता है। योग केवल एक स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या भर नहीं है, बल्कि यह पिछले कुछ वर्षों में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक निर्यात भी बन गया है।

आयुष मंत्रालय के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के पुनरुद्धार को संस्थागत बल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर पहुंचने में मदद मिली। समानांतर रूप से, सरकार ने संस्कृत, तमिल, पाली और प्राकृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं को संरक्षित करने, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और उस्ताद एवं हमारी धरोहर जैसी योजनाओं के तहत लुप्तप्राय लोक कलाओं और शिल्पों का समर्थन करने के लिए मिशन शुरू किए। भारत की ऐतिहासिकों इमारतों में भी नई जान आ गई। 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण केवल व्यापकता के बारे में नहीं था, बल्कि एक गाथा को पुनः प्रतिष्ठित करने जैसा था। सरदार वल्लभभाई पटेल लंबे समय से ओझल हो रहे थे। उनको राष्ट्रीय स्मृति में सबसे आगे रखा गया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक था। यह औपनिवेशिक प्रतीकवाद से देशी जवाबदेही की

2014 में शुरू से ही यह स्पष्ट था कि मोदी सरकार के तहत संस्कृति अब सजावटी नहीं रहेगी, बल्कि यह मूलभूत होगी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। अब दुनिया भर में लाखों लोगों को एक प्राचीन भारतीय परंपरा का जश्न मनाते देखा जा रहा है, जो शरीर, मन और आत्मा को आपस में जोड़ता है।

ओर बदलाव का भी प्रतीक था। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच 2019 की अनौपचारिक शिखर वार्ता की तुलना में शायद कोई भी कूटनीतिक वार्ता इस बदलाव को बेहतर तरीके से नहीं दशार्ती है। दिल्ली के गलियारों से दूर, प्राचीन बंदरगाह का नगर, जो कभी पल्लव राजवंश और भारत-चीनी समुद्री संबंधों का एक संपन्न केंद्र होने के साथ-साथ दो सभ्यताओं के बीच वार्ता की पृष्ठभूमि बन गया। जब नेता चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और पत्थर के रथों के बीच चले, तो भारत ने न केवल भूगोल, बल्कि इतिहास और न केवल प्रोटोकॉल, बल्कि विरासत को भी प्रस्तुत किया। यह अपने सबसे सूक्ष्म और सबसे मजबूत रूप में सॉफ्ट पावर था। यह सांस्कृतिक लोकाचार अन्य तरीकों से भी भारत की वैश्विक कूटनीति में प्रवाहित हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व के नेताओं को राजकीय उपहार के तौर पर पट्टचित्र पेंटिंग से लेकर बच्चों के लिए लाख के खिलौने भेंट किए गए, जो अपने साथ भारत के कारीगरों और कालातीत परंपराओं के संदेश लेकर गए।

2023 में जी-20 की अध्यक्षता एक और सांस्कृतिक उपलब्धि साबित हुई। दिल्ली के डिप्लोमेटिक हॉल तक सीमित न रहकर, यह शिखर सम्मेलन सांस्कृतिक पहचान का अखिल भारतीय उत्सव बन गया। आदिवासी कला प्रदर्शनों से लेकर शास्त्रीय प्रदर्शनों तक, भारत ने न केवल अपनी नीतिगत गहराई, बल्कि अपनी आत्मा का भी प्रदर्शन किया। हर प्रतिनिधिमंडल भारत के रंगों, व्यंजनों, शिल्प और चेतना में डूबा हुआ था। संदेश स्पष्ट थाः भारत भूतकाल की सभ्यता नहीं है - यह जीवंत, सशक्त और आत्मविश्वास से परिपूर्ण वैश्विक सभ्यता है। इन वर्षों के दौरान, 600 से अधिक चोरी की गई कलाकृतियां विदेशी संग्रहालयों और संग्रहकताओं से वापस लाई गईं, जिनमें मूर्तियां, शिलालेख और पांडुलिपियां शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक की वापसी न केवल कला की बल्कि सम्मान की बहाली थी। इसी तरह, गुरु गोविंद सिंह के वीर शहजादों की शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस की स्थापना की गई, जबकि जनजातीय गौरव दिवस ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय केन्द्र में लाया। महामारी भी सांस्कृतिक लौ को मद्धिम नहीं कर पाई। वर्चुअल कॉन्सर्ट, डिजिटल म्यूजियम टूर और 'मन की बात' के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि कला, कहानियां और सांस्कृतिक गौरव लॉकडाउन के एकांत में भी

'विकास भी, विरासत भी' के नारे जैसे अभियान में ये सभी समाहित हो गए। यह एक आह्वान है जो आर्थिक विकास को सांस्कृतिक गौरव के साथ-साथ चलने पर जोर देता है। मोदी सरकार के तहत, यह नारा केवल बयानबाजी नहीं था। इसने एक नई दृष्टि को परिभाषित किया।

पुष्पित-पल्लवित होते रहें।

'विकास भी, विरासत भी' के नारे जैसे अभियान में ये सभी समाहित हो गए। यह एक आह्वान है जो आर्थिक विकास को सांस्कृतिक गौरव के साथ-साथ चलने पर जोर देता है। मोदी सरकार के तहत, यह नारा केवल बयानबाजी नहीं था। इसने एक नई दृष्टि को परिभाषित किया। एक दृष्टि, जिसमें जीडीपी वृद्धि, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा आधुनिकीकरण, मंदिर जीर्णोद्धार, आदिवासी गौरव और सभ्यता की गाथा समाहित थे।

भारत आज अपनी पहचान के इर्द-गिर्द नहीं घूमता। बिना किसी पछतावें और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर यह आगे बढ़ता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्रगति की बाध्यकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसे कभी प्रतिगामी के रूप में खारिज कर दिया गया था। भाजपा के वैचारिक कम्पास में, संस्कृति केवल एक सहायक भर नहीं है, बल्कि धुरी है।

इन ग्यारह सालों में मोदी युग ने केवल सांस्कृतिक नीति को ही ध्यान में नहीं रखा है, बल्कि इसने सांस्कृतिक चेतना को भी जागृत किया है। जो पुनर्स्थापना के तौर पर शुरू हुआ था, वह पुनरुत्थान बन गया। जिन्हें कभी अतीत की स्मृतियों के तौर पर उपेक्षित किया जाता था, वे सभी अब राष्ट्रीय पहचान के केंद्र बन गए हैं।

राम मंदिर और सेंगोल हमेशा सांकेतिक प्रतीक बने रहेंगे, लेकिन विरासत की गहराई सामूहिक अहसास में निहित है। भारत का भविष्य तब सबसे उज्ज्वल होगा, जब वह याद रखेगा कि वह कहां से आया है। हम सिर्फ एक लंबा इतिहास वाला देश नहीं हैं, बल्कि हम एक लंबी स्मृति वाली जीवित सभ्यता हैं। और उस स्मृति में, धर्म की निगरानी में, भारत ने फिर से अपनी आवाज पाई है।

अहमदाबाद विमान दुर्घटना दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण

गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसा रोंगटे खड़े करने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले हमें आसमान में काला धुआं दिखा, तो लगा कि कहीं आग लगी होगी। इसके बाद पता चला कि एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। विमान में बहुत से लोग सवार थे। ऐसे में किसी का बच पाना मुश्किल था। घटनास्थल से महज दो किलोमीटर दूर रहने वाले जयराम रमेश ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि प्लेन क्रैश के बारे में आसपास के लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, तो सभी सहम गए। पहले बताया गया कि एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया, कोई भी बच नहीं पाएगा। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक था। हादसे में किसी के भी बचे होने की उम्मीद ना के बराबर है। यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे। ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। आश्चर्य जनक केवल यह है कि इसमें से एक यात्री बच गया।

दुनियाभर के विमानों पर नजर रखने वाली फ्लाइट रडार के मुताबिक, प्लेन ने दोपहर 1.38 बजे उड़ान भरी थी। प्लेन का एक वीडियो वायरल हो गया है। इसमें लैंडिंग गियर (टायर) खुले दिखाई देते हैं। विमान धीरे-धीरे नीचे जाता है और आग की लपटें उठने लगती हैं। लंदन के लिए लंबी दूरी की उड़ान टेकऑफ से पहले ईंधन से भरी हुई थी।

चरण सिंह

वीडियो देखने से एक बात साफ है कि विमान को इंजन से थ्रस्ट (ऊपरी शक्ति) नहीं मिलती है और वह ऊंचाई नहीं बढ़ा सकता है।

वीडियो में इंजन में आग या धुआं नहीं दिख रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि पक्षियों का झुंड विमान से टकराया और इंजन में फंस गया। विमान के कॉकपिट की जांच से दुर्घटना के सही कारण का पता चलेगा। अहमदाबाद हवाई अड्डे के बंद होने का मतलब है कि जांच दल रनवे की जांच कर सकता है। उसका भी पता लगाया जा रहा है। टेक-ऑफ के दौरान हुआ हादसा भयानक है। क्योंकि यह ईंधन से भरा है। वीडियो देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि विमान के पंख सपाट हैं और संतुलन ठीक है; लेकिन यह नीचे गिर रहा है। इससे पता चलता है कि विमान ऊंचाई खो रहा है।

उसे ऊपर जाने के लिए इंजन से बिजली नहीं मिलती है। विमान के टेक-ऑफ में एक गंभीर चरण होता है। यहां तक कि अगर पायलट को इसे पार करने के बाद कोई समस्या मिलती है, तो भी वह टेक-ऑफ को रोक नहीं सकता है। क्योंकि उस स्थिति में अधिक नुकसान हो सकता है। यदि विमान का एक इंजन काम कर रहा है, तो पायलट विमान को ऊंचाई पर ले जा सकता था और आपात स्थिति में उसे उतार सकता था। इसका मतलब है कि विमान के दोनों इंजन विफल हो गए और वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह किसी त्रुटि या विद्युत विफलता के कारण हो सकता है। विमान उड़ाते समय V1 और V2 गति होती है। V1 गति में, पायलट उड़ान भरने का फैसला करता है। रनवे छोड़ने के बाद, V2 गति के दौरान टेक-ऑफ को रद्द नहीं किया जा सकता है। एयर इंडिया के विमान ने रनवे से उड़ान भरी, जिसका अर्थ है कि V1 गति तक सब कुछ ठीक था। पायलट ने ध्2 गति के साथ एक समस्या देखी होगी; लेकिन आपातकाल के बाद भी वह उड़ान रद्द नहीं कर सके। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद पायलट ने मेयडे कॉल का मैसेज एटीसी को भेजा, जिसके बाद संपर्क टूट गया, इसलिए फ्लाइट में दिक्कत का तुरंत पता नहीं चल सका। लेकिन दुर्घटना के समय विमान के लैंडिंग गियर (टायर) उजागर हो गए थे और टेक-ऑफ के समय विंग फ्लैप स्थिति में थे; लेकिन पायलट विमान को 600 से 700 फीट की ऊंचाई पर नहीं उठा पाया। दोनों इंजनों से बिजली न मिलने के कारण उसने विंग लेवल को मेंटेन करते हुए असाधारण उड़ान कौशल दिखाया है।

पायलट के अनुभव में, इस दुर्घटना में मानवीय त्रुटि की संभावना बहुत कम लगती है। यहां तक कि अगर एक इंजन विफल हो जाता है, तो विमान को दूसरे इंजन पर संभाला जा सकता है। विमान दुर्घटना का मतलब है कि दोनों इंजन बिजली प्रदान नहीं कर सकते हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना से पहले

पायलट ने तीन बार संकेत दिया। अधिकांश आधुनिक विमानों में कंप्यूटर नियंत्रित इंजन होते हैं। इसलिए, कोई कारण नहीं बताया जा सकता है कि इंजन काम क्यों नहीं करता है। एक कारण ईंधन हो सकता है। लेकिन इस विमान में उनमें से बहुत सारे थे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पाइपलाइन में ब्लॉक होने के कारण इंजन तक ईंधन नहीं पहुंच रहा था। तीसरा कारण यह हो सकता है कि कंप्यूटर को सही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं मिले। लंदन के लिए उड़ान भरने से पहले विमान अहमदाबाद में कुछ घंटों के लिए जमीन पर था। माना जाता है कि एयर इंडिया के इंजीनियरों ने इस अवधि के दौरान सब कुछ देखा है। दूसरी ओर, एयरलाइंस का लक्ष्य हवाई यातायात में वृद्धि के कारण विमान और श्रमिकों का उपयोग करने वाली एयरलाइनों की लागत को कम करना है। पायलटों और कर्मचारियों के पास अब लंबे समय तक काम करने का सप्ताह है और इसलिए अधिक कार्यभार है। परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

थकान से संबंधित सुरक्षा दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और कर्मचारी अब परिचालन संबंधी त्रुटियों को जिम्मेदार ठहराते हैं जैसे कि गलत रनवे पर उतरना या ईंधन को गलत तरीके से पढ़ना तनाव और नींद की कमी को जिम्मेदार ठहराता है। भारतीय एयरलाइनों की सुरक्षा अन्य एयरलाइनों की तुलना में दुनिया के समग्र विमानन में कुछ हद तक उपेक्षित है। हालांकि, विमान दुर्घटनाओं की संख्या में कमी नहीं आई है, पिछले दो दशकों में 21-23 प्रतिशत प्रमुख विमान दुर्घटनाओं को जांच का एक संभावित कारण निर्धारित किया गया है। 2020 में, यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी ने बड़े विमानों के लिए शीर्ष सुरक्षा समस्या के रूप में 'बड़े विमानों के लिए कल्याण और फिटनेस स्थिति' की पहचान की। 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की भयानक दुर्घटना इस बात का उदाहरण है कि पायलट की थकान का विमान के सुरक्षित संचालन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब मंगलुरु में उतरते समय 166 यात्रियों को ले जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 158 लोग मारे गए। वास्तव में, कप्तान के खराटों की आवाज को पहली बार कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन में किसी भी भारतीय एयरलाइन का नाम नहीं लिया गया है। हर साल, एयरलाइन विशेषज्ञों की एक टीम दुनिया में 400 एयरलाइनों की सुरक्षा की जांच करती है। यह पिछले दो वर्षों में 400 एयरलाइनों की सुरक्षा का आकलन करती है। विमान दुर्घटनाओं की संख्या, दुर्घटनाओं की कुल संख्या, सरकारी रिपोर्ट, जीवन और विमान की संख्या, पायलट प्रशिक्षण की गुणवत्ता और एयरलाइन की वित्तीय स्थिति। कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में एक भी भारतीय एयरलाइन का नाम नहीं लिया गया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय यात्री हवाई यात्रा में कितने सुरक्षित हैं। हालांकि, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को कम लागत वाली एयरलाइनों की सूची में 19वां स्थान दिया गया है। पांच अमेरिकी एयरलाइंस को इस वर्ष शीर्ष 24 सबसे सुरक्षित एयरलाइनों में शामिल किया गया है, जिसमें फ्रंटियर (नंबर 5), साउथवेस्ट (नंबर 9), सन कंट्री (नंबर 15), जेटब्लू (नंबर 17) और एलिगेंट एयर (21 वां) शामिल हैं। यह हर साल 400 एयरलाइनों का विश्लेषण करता है और उनके विभिन्न सुरक्षा मानकों की जांच करता है। यह प्रमुख दुर्घटनाओं, कुल घटना आवृत्ति, हाल की दुर्घटनाओं, विमान की जीवन प्रत्याशा, लेखा परीक्षा और विमान की कुल संख्या, पायलट प्रशिक्षण की गुणवत्ता और वित्तीय स्थिति के आधार पर रेटिंग देता है। किसी भी कंपनी में वित्तीय अस्थिरता एयरलाइन के लिए गंभीर परिचालन चुनौतियां पैदा कर सकती है। उसकी सुरक्षा रैंकिंग भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइंस इस सूची में जगह नहीं बना पाती हैं। भारत मे जैसे कि पहले बताया विमान दुर्घटना के चार्ट में कुछएक दुर्घटनाओं को छोड़ कर नंबर बहुत ही पीछे है । देखा जाय तो घाटकोपर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान एक छोटा चार्टर विमान था। किंग एयर चार्टर विमान एक परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत में पहली विमान दुर्घटना 1938 में हुई थी। मध्य प्रदेश के दतिया के पास एयर फ्रांस पोटेज विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सात लोग मारे गए। पिछले 15 वर्षों में भारत की दूसरी बड़ी दुर्घटना मई 2010 में कर्नाटक के मंगलुरु में हुई थी। फरवरी 1990 में, एक एयरबस ए 320 रनवे से फिसल गया और बेंगलुरु में उतरते समय एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 92 लोग मारे गए। पायलट की गलती से अब तक कई दुर्घटनाएं हुई हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 को तब आयरलैंड के तट से अटलांटिक महासागर में एक बम विस्फोट में उड़ा दिया गया था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। पायलट की गलती को विमान दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। दुर्घटनाएं तब होती हैं जब पायलट टेकऑफ के दौरान रनवे की गति, लिफ्ट-ऑफ पॉइंट या पिच कोण को गलत समझते हैं।

अंतरराष्ट्रीय विमानन रिपोर्टों के अनुसार, दुनिया भर के आंकड़ों के अनुसार, टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण मानवीय त्रुटि भी रही है, जिसमें 65% टेकऑफ दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटि के कारण, तकनीकी विफलताओं के कारण 20%, मौसम के कारण 10% और अन्य कारणों से 5% हैं।अहमदाबाद विमान दुर्घटना का पायलट सुमित सभरवाल आज दुनिया में नहीं है। यह कहना संभव नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना चाहिए। जीवन की लागत बहुत बड़ी है। यह एक पल में संभव नहीं था। विमान दुर्घटना में ऐसा हो सकता है। एयरलाइंस के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी हादसों से बचने के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा ने दिया भारत विरोधी ताकतों को कड़ा संदेश

साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारोयिस' से सम्मानित किया।' इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के प्रथम चरण में साइप्रस पहुंचे। उनकी यह यात्रा रणनीतिक तथा सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रही । प्रधानमंत्री ने अपनी साइप्रस की इस यात्रा से कई रणनीतिक उद्देश्य पूर्ण किए हैं । इस यात्रा से आपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्किए के शासनाध्यक्ष एदोर्गान को कठिनाई होने वाली है। साइप्रस सामरिक, रणनीतिक व कूटनीतिक दृष्टिकोण से

राहुल अग्रवाल

भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी साइप्रस का दौरा किया था।

साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारोयिस' से सम्मानित किया।' इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे व वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। इसके साथ ही पीएम मोदी को सम्मानित करने वाले देशों की संख्या 22 हो गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस के विजन -2035 और विकसित भारत के विजन-2047 के कई पहलुओं से समानता है। हम साथ मिलकर भविष्य को आकर देंगे। 23 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य रक्षा, वित्त, व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई।

साइप्रस ने संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया और आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मिलकर संयुक्तराष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकियों, आतंकी संगठनों और उन्हें पनाह देने वालों, उनके लिए छद्म तरीके से काम करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी अपील की है। साइप्रस ने आतंकवाद

के खिलाफ लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर का भी पुरजोर समर्थन किया।

प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने तुर्किए के कब्जे वाले साइप्रस के भूभाग के पास वाले क्षेत्र का भ्रमण किया और तुर्किए को संदेश देते हुए कहा कि भारत साइप्रस गणराज्य की स्वतंत्रता, संप्रभुता, भौगोलिक अखंडता और एकता को अटल व सतत समर्थन देता रहेगा। इसके लिए वह किसी एक पक्ष की तरफ से मनमाने तरीके से कदम उठाए जाने पर रोक लगाने व सार्थक वार्ता का वातावरण बनाए जाने का समर्थन करता है।

तुर्किए ने 1974 से साइप्रस के लगभग एक तिहाई हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। तुर्किए कश्मीर मुद्दे पर बार- बार पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी करता है, ऑपरेशन सिंदूर के समय उसने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना युद्धपोत भेजा, भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन दिये उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वाभाविक रूप से स्पष्ट संदेश दिया कि अब भारत साइप्रस की संप्रभुता का पूर्ण समर्थन कर रहा है।

साइप्रस और भारत एक दूसरे के परिस्थितिगत साथी हैं। साइप्रस तुर्किए से उलझा हुआ देश है। भारत -साइप्रस के मजबूत होते संबंधों को तुर्किए के खिलाफ कूटनीतिक बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। साइप्रस का रुख सदा से भारत के समर्थन में रहा है। साइप्रस को भूमध्य सागर और यूरोप में प्रवेश का गेटवे कहा जाता है। यह सीरिया और तुर्किए के करीब है। भौगोलिक रूप से एशिया में होने के बावजूद इसे यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में दर्जा मिला हुआ है । यही वजह है कि यूरोप के साथ संपर्क बनाने में भारत के लिए यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। साइप्रस भारत के लिए व्यापार, निवेश और रणनीतिक संवाद पर के लिए भी अहम है।यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार संधि के लिए साइप्रस एक महत्वपूर्ण भागीदार व सहायक हो सकता है।

साइप्रस भारत के लिए निवेश के हब रहा है। आर्थिक और कानूनी रूप से सुरक्षित निवेश हब के तौर पर यह भारत के लिए सदा से ही लाभदायक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान व्यवसायियों को एनर्जी टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य

साइप्रस को रणनीतिक आर्थिक गलियारे में और अधिक मजबूती से जोड़ना है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य रूप में साइप्रस ब्लॉक में भारत के हितों का समर्थन करने में अहम भूमिका निभा सकता है। साइप्रस भूमध्य सागर में है जहां गैस तेल संसाधन की अपार संभावनाएं हैं । साइप्रस की मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक स्थिर सहयोग दे सकता हैं। अपने ऊर्जा स्त्रोतों में विविधता लाने में भारत की रुचि साइप्रस को ऊर्जा साझेदारी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। इस यात्रा के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी निकोसिया में संघर्ष विराम रेखा के पास एक ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचे तो निकोसिया म्यूनिसिपल काउंसिल के एक सदस्य मिछेला किथेरियोटी मालपा ने सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए। इससे पता चलता है कि पूरे विश्व में भारत व प्रधानमंत्री मोदी का कितना सम्मान है।

जातिगत जनगणना: आर्थिक और सामाजिक योजनाओं की रीढ़!

बीते दिनों केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी जो अपने आपमें स्वागतयोग्य कदम है, क्योंकि 'जो दिखता नहीं, वो गिना नहीं जाता और जो गिना नहीं जाता, वो सत्ता और संसाधनों की दौड़ में कहीं पीछे छूट जाता है।' भारत में जाति एक सामाजिक सत्य है, जिसे नजरअंदाज करना असंभव है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जाति भारतीय समाज की संरचना, अवसरों की उपलब्धता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों के वितरण का निर्धारक बनी हुई है। ऐसे में जातिगत जनगणना केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में पहली बार व्यवस्थित जातिगत जनगणना 1871 में की गई थी, जिसे बाद की जनगणनाओं में 1931 तक जारी रखा गया। लेकिन 1951 के बाद से स्वतंत्र भारत में जातिगत आंकड़ों को जानबूझकर इकट्ठा नहीं किया गया। केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गणना होती

रवि जैन

रही। 1931 के बाद से ओबीसी की जनसंख्या का कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी आबादी का अनुमान 52 फीसदी लगाया था, पर यह अनुमान आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं रह गया है। लगभग एक सदी पुराने आंकड़ों के आधार पर सामाजिक न्याय की नीतियां बनाना न केवल अवैज्ञानिक है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध भी है।

सामाजिक न्याय की दृष्टि से अनिवार्यता

जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए आधारभूत आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि कौन सी जातियाँ कितनी संख्या में हैं, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल आरक्षण देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, सम्मान और भागीदारी प्राप्त हो। जब तक पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का आंकलन नहीं होगा, तब तक नीतियों की प्रभावशीलता संदेहास्पद रहेगी। जातिगत जनगणना के बिना यह जानना संभव नहीं कि-

- कौन सी जातियाँ आरक्षण का वास्तविक लाभ ले रही हैं?
- किन समुदायों को आज भी हाशिए पर रखा गया है?
- क्या वर्तमान आरक्षण नीति सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूरा कर रही है?

आर्थिक आधार बनाम जाति आधारित असमानता

आर्थिक आधार पर पिछड़ापन तय करने की मांग लगातार उठती रही है। लेकिन भारतीय संदर्भ में यह तर्क अधूरा है। गरीब तो सभी वर्गों में हो सकते हैं, लेकिन हर गरीब की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती। एक सवर्ण गरीब और एक दलित गरीब के बीच जमीन-आसमान का फर्क होता है। दलित

या ओबीसी गरीब को सामाजिक भेदभाव, उत्पीड़न, और प्रतिनिधित्व आदि वंचनाओं का सामना करना पड़ता है। इसके उलट, सवर्ण गरीब को सामाजिक नेटवर्क, सम्मान और अवसरों की सांस्कृतिक पूंजी प्राप्त होती है। इसलिए केवल आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाना, जातिगत असमानताओं की अनदेखी करना है। जाति और आर्थिक स्थिति दोनों को समग्रता में समझना होगा। और इसके लिए जातिगत आंकड़े अनिवार्य हैं।

संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रश्न

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा निहित है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करे, लेकिन सवाल यह है कि बिना आंकड़ों के हम यह कैसे तय करेंगे कि पिछड़ा वर्ग कौन है और कितना पिछड़ा है? क्या यह उचित है कि 90 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर 140 करोड़ की आबादी के लिए नीतियां बनाई जाएं? जातिगत जनगणना संविधान की उस आत्मा को सशक्त करती है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात करती है। लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को बराबरी के अवसर देना भी है।

राजनीतिक संदर्भ और सत्ता की जटिलता

जातिगत जनगणना केवल सामाजिक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी है। यह चुनावी गणित और सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि केंद्र की सरकारें वर्षों से इसे टालती रही हैं। अगर जातिगत आंकड़े सामने आ जाए और यह साबित हो जाएगा कि ओबीसी वर्ग की आबादी 50 फीसदी से कहीं अधिक है, तो यह मांग उठेगी कि आरक्षण भी उस अनुपात में बढ़ाया जाए। इससे संविधान में तय 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा (इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, 1992) को चुनौती दी जा सकती है। यह राजनीतिक दलों, खासकर सत्तारूढ़ दलों के लिए असहज स्थिति पैदा करता है। बीजेपी जैसी पार्टी, जो एक ओर तो ओबीसी नेतृत्व को उभारने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर उच्च जातियों के पारंपरिक वोट बैंक को भी बनाए रखना चाहती है। ऐसे में जातिगत जनगणना उनके लिए ह्यडबल एज्ड स्वॉर्डह्ल बन जाती है।

बिहार का उदाहरण: एक साहसी कदम

2023 में बिहार सरकार ने एक साहसी निर्णय लेकर जातिगत सर्वेक्षण कराया। इसमें यह सामने आया कि ओबीसी और ईबीसी की संयुक्त आबादी 63 फीसदी से अधिक है। यह आंकड़ा सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार के इस कदम ने यह दिखा दिया कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो जातिगत गणना संभव है। साथ ही इसने अन्य राज्यों और केंद्र सरकार पर नैतिक दबाव भी बनाया कि वे भी यह पहल करें। इस सर्वेक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि ओबीसी और ईबीसी वर्गों के भीतर भी भारी विषमता है। कुछ जातियाँ बार-बार प्रतिनिधित्व पा रही हैं, जबकि कई अभी भी उपेक्षित हैं। यह ह्यसामाजिक न्याय के भीतर न्यायह्ल की मांग को जन्म देता है।

जातिवाद बनाम जाति चेतना

जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले अक्सर यह तर्क देते हैं कि इससे समाज में जातिवाद बढ़ेगा। लेकिन यह सत्य नहीं है। जातिवाद तब तक रहेगा जब तक सामाजिक असमानताएं रहेंगी। जातिगत आंकड़ों को सामने लाना इन असमानताओं से लड़ने का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है। जातिगत जनगणना जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि उसे तर्क, आंकड़ों और योजनाओं के माध्यम से चुनौती देती है। यह एक उत्तरदायी और जागरूक लोकतंत्र की निशानी है कि वह अपने भीतर की असमानताओं को न केवल देखे, बल्कि उन्हें स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम भी उठाए।

नीति निर्माण, बजट और योजनाओं में भूमिका

सरकार जब भी कोई योजना बनाती है, तो उसका लाभ किन्हें मिलेगा, यह आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। लेकिन जब जातिगत आंकड़े ही उपलब्ध नहीं हैं, तो यह कैसे सुनिश्चित होगा कि योजनाएं वंचितों तक पहुँच रही हैं?

जातिगत जनगणना से:

- योजनाओं का लक्षित क्रियान्वयन संभव होगा,
- बजट आवंटन अधिक न्यायपूर्ण होगा,
- आरक्षण की समीक्षा और पुनर्संरचना के लिए मजबूत आधार मिलेगा,
- और सामाजिक समरसता के लिए ठोस रणनीति बन सकेगी।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत की अलग स्थिति

अक्सर कहा जाता है कि दुनिया के किसी लोकतंत्र में जाति आधारित जनगणना नहीं होती, तो भारत में क्यों हो? लेकिन भारत की सामाजिक संरचना अद्वितीय है। पश्चिमी समाजों में जातिगत भेदभाव जैसी जटिलताएँ नहीं हैं। वहाँ नस्लीय या क्षेत्रीय आधार पर गणनाएँ होती हैं। भारत में जाति जन्म से जुड़ी सामाजिक स्थिति को परिभाषित करती है। यहाँ तक कि विवाह, पेशा, शिक्षा, और राजनीतिक पहुँच भी जाति से जुड़े हैं। इस वास्तविकता को नकारना आत्मवंचना है।

समावेशी विकास की कसौटी

'सबका साथ, सबका विकास' और 'सबका विश्वास' तभी संभव है जब हम जानें कि कौन अब तक विकास की मुख्यधारा से बाहर रहा है।

जातिगत जनगणना से:

- नीति निर्माण अधिक समावेशी होगा,
- योजनाएं धरातल पर प्रभावशाली ढंग से उतरेंगी,
- और लोकतंत्र में सहभागिता का स्तर बढ़ेगा।

जातिगत जनगणना केवल संख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व, भागीदारी और अवसरों की समानता का आधार है।

ऐसे में जातिगत जनगणना को लेकर जो भ्रम और भय फैलाए जाते हैं, वे वास्तव में सत्ता के भीतर छिपी असहजता को दिखाते हैं। यदि भारत को वाकई में सामाजिक न्याय पर आधारित समावेशी लोकतंत्र बनाना है, तो उसे अपनी सच्चाइयों से डरना नहीं, उन्हें स्वीकार करना होगा। जातिगत जनगणना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में एक तार्किक और आवश्यक कदम है। यह इस देश के करोड़ों नागरिकों को यह विश्वास दिलाने का माध्यम बन सकती है कि उनकी गिनती भी लोकतंत्र में मायने रखती है। सवाल यह नहीं है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि अब तक क्यों नहीं हुई? और अब समय आ गया है कि भारत अपने भीतर झांके, खुद को गिने, और सबको गिन कर ही सबको साथ लेकर चले, क्योंकि भारत जैसे विविधता से भरे देश में, जहां जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि अवसरों, संसाधनों और सत्ता तक पहुंच की कुंजी बन चुकी है, वहां जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की बुनियाद है।

समाजवादी पार्टी में 'पीडीए' की रक्षा या अनुशासन का दिखावा?

इंद्रेश शर्मा

समाजवादी पार्टी ने जिस अंदाज में अपने तीन बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ यह अनुशासन का संदेश है, तो दूसरी ओर जातीय समीकरणों का राजनीतिक संतुलन भी। लेकिन बात सिर्फ निष्कासन की नहीं है, असली सवाल यह है कि सात में से केवल तीन पर ही कार्रवाई क्यों हुई? यह निर्णय सिर्फ पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर नहीं, बल्कि रणनीतिक और सामाजिक गणनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। अखिलेश यादव की इस 'आंशिक कार्रवाई' के केंद्र में एक नई समाजवादी राजनीति आकार ले रही है, जो पुराने मुलायम युग से अलग दिखती है, लेकिन उतनी ही संवेदनशील भी है। अखिलेश यादव ने अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक डॉ. मनोज पांडे को निष्कासित कर पार्टी का संदेश स्पष्ट कर दिया कि भीतरघात अब बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इससे भी बड़ा संदेश यह गया कि जिन लोगों ने न केवल भाजपा के पक्ष में वोट डाला, बल्कि पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते रहे, उनके लिए सपा में अब कोई जगह नहीं है। ये तीनों विधायक एक लंबे समय से सार्वजनिक मंचों पर अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। मनोज पांडे ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने एक साल पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी और अब सपा की कार्रवाई से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह लगातार सपा को 'हिंदू विरोधी' और 'रामविरोधी' पार्टी करार देते रहे हैं। ऐसे में इन पर कार्रवाई न करना अखिलेश के लिए अपनी साख और नेतृत्व दोनों पर सवालिया निशान बन सकता था।

लेकिन जिस तरीके से बाकी चार विधायकों को पार्टी में बरकरार रखा गया है, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सपा में कार्रवाई भी अब जाति देखकर तय होती है? दरअसल, जिन तीनों को निकाला गया, वे सभी सवर्ण हैं मनोज पांडे ब्राह्मण और बाकी दो ठाकुर। वहीं पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, विनोद चतुर्वेदी और राकेश पांडे में से दो पिछड़ी जातियों से हैं और दो ब्राह्मण हैं, जिनका पार्टी विरोधी बयान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। यही वह अंतर है जो अखिलेश यादव की रणनीति को जातीय गणित से जोड़ता है। सपा इन दिनों 'पीडीए' यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में उन विधायकों को तुरंत बाहर करना जिन्हें पार्टी अभी अपने जनाधार से जोड़कर देख रही है, सियासी आत्मघात हो सकता था।

पूजा पाल और आशुतोष मौर्य जैसे नेता न सिर्फ ओबीसी वोट बैंक में सपा के लिए सहायक हो सकते हैं, बल्कि इनका निष्कासन समाजवादी पार्टी को उस वर्ग से और दूर कर सकता था, जिसे जोड़ने के लिए पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। वहीं ब्राह्मणों को लेकर अखिलेश का रुख अभी भी संतुलित है। 2022 के चुनावों में ब्राह्मणों को जोड़ने की नाकाम कोशिशों के बाद भी पार्टी उन्हें पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि विनोद चतुर्वेदी और राकेश पांडे जैसे ब्राह्मण विधायकों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह रणनीति सधी हुई है ना सवर्णों को पूरी तरह नाराज करना है, ना ही कोर वोट बैंक को जोखिम में डालना है।

लेकिन सवाल सिर्फ जाति का नहीं है। व्यवहार और भाषा भी उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं। जिन तीन विधायकों को निकाला गया, उन्होंने सिर्फ पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग नहीं की, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी इंटरव्यू तक में अखिलेश यादव को कमजोर, अहंकारी और जातिवादी नेता बताया। ये लोग भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करते रहे और अपने क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह सक्रिय रहे। वहीं बाकी चार ने भले ही वोट भाजपा को दिया हो, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर चुप्पी साधे रखी। राजनीति में चुप्पी अक्सर सजा से बचा लेती है, और यही इन विधायकों के साथ हुआ।

सपा की यह आंशिक कार्रवाई पार्टी अनुशासन की मजबूती भी दर्शाती है और आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को भी। अखिलेश यादव यह अच्छी तरह जानते हैं कि 2027 का चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग प्वाइंट हो सकता है। ऐसे में उन्हें पार्टी के भीतर विश्वासघात से ज्यादा अपने जनाधार की एकता चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने ऐसे लोगों को पहले निशाने पर लिया, जिनके जाने से पार्टी को वोटों का नुकसान नहीं होगा। ठाकुर और ब्राह्मण विधायक जो अब भाजपा की ओर झुक चुके हैं, उन्हें बाहर निकालकर अखिलेश ने सपा के अंदर एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि होगा।

भाजपा ने इस मुद्दे को लपकने में देर नहीं लगाई। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा अब अपने ही कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है और पार्टी पूरी तरह बिखर चुकी है। लेकिन भाजपा को भी यह मालूम है कि सपा की यह कार्रवाई केवल अनुशासन नहीं बल्कि रणनीतिक शुद्धिकरण है। सपा अब पुराने ढांचे को तोड़कर नई सामाजिक गठजोड़ तैयार कर रही है, जिसमें जाति, विचारधारा और निष्ठा का संतुलन अहम है। कुल मिलाकर, समाजवादी पार्टी ने तीन विधायकों को निष्कासित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी में अब केवल संख्या नहीं, विचारधारा और व्यवहार भी अहम होगा। लेकिन जो चार विधायक फिलहाल बचे हुए हैं, उन पर नजरें टिकी रहेंगी। अगर ये लोग भी भविष्य में पार्टी लाइन से हटते हैं या भाजपा से नजदीकी बढ़ाते हैं, तो यह तय माना जा रहा है कि अगली सूची में उनके नाम भी होंगे। फिलहाल अखिलेश यादव ने एक सधी हुई सियासी चाल चली है, जिससे पार्टी के भीतर अनुशासन भी कायम हो और जातीय संतुलन भी न बिगड़े। यह चाल चुनावी शतरंज की तैयारी है, जहां हर मोहरा अब पार्टी लाइन से ही चलेगा।

दरअसल, जिन तीनों को निकाला गया, वे सभी सवर्ण हैं मनोज पांडे ब्राह्मण और बाकी दो ठाकुर। वहीं पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, विनोद चतुर्वेदी और राकेश पांडे में से दो पिछड़ी जातियों से हैं और दो ब्राह्मण हैं, जिनका पार्टी विरोधी बयान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया।

दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'कैशलेस' उपचार: नीयत नेक, व्यवस्था बेकार

इस देश में जब कोई सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो सबसे पहले यह नहीं पूछा जाता कि जख्म कितना गहरा है-पहले यह पूछा जाता है कि 'पहचान पत्र है?', 'बीमा है?', 'अस्पताल पंजीकृत है?' और फिर अंत में-'बचा पाएँगे या नहीं?'। मानो पीड़ित की जान से पहले कागज जरूरी हो।

अनिल वशिष्ठ

ऐसे देश में जब सरकार यह कहती है कि 'अब किसी भी सड़क हादसे में घायल को पहले सात दिन ₹1.5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा', तो लगता है जैसे व्यवस्था ने कोई इंसानी चेहरा पहन लिया है। लेकिन जब जमीन पर उतरकर इस योजना की हकीकत देखते हैं, तो वो चेहरा धुंधला दिखता है – कभी फाइलों में खोया, कभी पोर्टल में अटका, और कभी अस्पताल की बेरुखी में दम तोड़ता।

यह नकदरहित उपचार योजना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 162 के तहत शुरू की गई थी। उद्देश्य यही था कि किसी गरीब या अमीर को इलाज के लिए अपनी जेब नहीं टटोलनी पड़े। पहली दृष्टि में यह लगता है कि सरकार ने आम जन की पीड़ा को समझा है। लेकिन फिर वही पुराना सवाल उठता है – क्या नीयत और नीति के बीच की दूरी को व्यवस्था कभी पाट पाएगी?

अभी तक कई राज्यों ने तो इस योजना को लागू करने के आदेश ही नहीं दिए हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद जैसे विकसित क्षेत्रों में भी जून 2025 तक अस्पतालों को पता ही नहीं था कि योजना चालू हो चुकी है। क्या ये हास्यास्पद नहीं कि योजना चालू हो गई है लेकिन अस्पताल और डॉक्टर उसे ढूंढ़ रहे हैं जैसे कोई खोया हुआ यातायात संकेत?

और जो अस्पताल योजना से जुड़े भी हैं, वहाँ इलाज की सीमा ₹1.5 लाख की है। अब जरा

सोचिए – एक गंभीर सड़क हादसे में भर्ती मरीज का आईसीयू, सर्जरी, दवाइयाँ, जांच – क्या ये सब ₹1.5 लाख में सिमट सकते हैं? निजी अस्पतालों ने तो साफ कहा है- 'हमें घाटे में क्यों काम करना चाहिए?' और सरकार जवाब देती है-'देशसेवा!' लेकिन क्या देशसेवा खाली डॉक्टरों की ज़िम्मेदारी है? नीति निर्धारकों की नहीं?

संकट सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। पोर्टल- हाँ वही कम्प्यूटर पर बना पोर्टल-जिसे देखकर अस्पताल का बाबू भी माथा पकड़ ले। कभी दस्तावेज अपलोड नहीं होते, कभी फार्म अधूरा रह जाता है, और कभी पूरा क्लेम 'त्रुटि' में चला जाता है। मरीज तो क्या, अस्पताल तक को नहीं मालूम होता कि किससे संपर्क करें, कहाँ सुधार करवाएँ।

अस्पताल, पुलिस, बीमा एजेंसियाँ और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण-सबके पास अलग-अलग नियम, अलग-अलग समझ, और एक जैसी असमंजस है। कोई नहीं जानता किसका क्या काम है। लगता है जैसे योजना एक मंचन है जिसमें सभी पात्र हैं, लेकिन किसी को पटकथा नहीं दी गई।

और तो और, कई बार दुर्घटना इतनी गंभीर होती है कि आसपास के जो अस्पताल हैं, वे योजना में पंजीकृत नहीं होते। ऐसे में वे 'स्थिति स्थिरीकरण' भी करने से डरते हैं-उन्हें डर है कि कहीं पैसा न फँस जाए! परिणाम-घायल मरीज एंबुलेंस में इधर से उधर ढोया जाता है, और उसका 'गोल्डन ऑवर' यानी जीवन बचाने का सबसे कीमती समय-रास्तों में ही बीत जाता है।

अब बात करें सबसे बुनियादी लेकिन सबसे उपेक्षित पक्ष की-जागरूकता। जनता को नहीं पता कि ऐसी कोई योजना है। सड़क पर पड़ी एक घायल महिला को देखकर लोग कैमरा तो निकाल लेते हैं, लेकिन इलाज के लिए योजना का नाम नहीं बता पाते। अस्पताल में कार्यरत स्टाफ तक को नहीं मालूम होता कि कैसे योजना को लागू किया जाए। योजना का लाभ तब मिलेगा जब लाभार्थी को पता ही नहीं कि वो लाभार्थी है?

हास्य तब और गहरा हो जाता है जब सरकार 'राहवीर योजना' के तहत ₹25,000 तक इनाम देती है किसी घायल की मदद करने पर – लेकिन योजना की जानकारी लोगों को रेडियो या सरकारी पोस्टर तक सीमित है। सोशल मीडिया पर जहाँ लोग नाचते-गाते दिखते हैं, वहाँ ये योजना अदृश्य है। योजना को जमीन पर सफल बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। सबसे पहले- राज्य सरकारें आलस्य त्यागें और स्पष्ट दिशानिर्देश दें। अस्पतालों को स्पष्ट समय सीमा में पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। इंदौर का उदाहरण अच्छा है जहाँ जून 2025 में तीन दिन के भीतर अस्पतालों को योजना में शामिल कर लिया गया।

दूसरे, योजना की वित्तीय सीमा वास्तविक चिकित्सा लागतों के अनुसार तय की जाए। अगर सरकार लोगों की जान बचाना चाहती है, तो अस्पतालों को घाटे में क्यों धकेल रही है?

तीसरे, पोर्टल को 'डिजिटल इंडिया' का मजाक बनने से बचाना होगा। यह सरल, स्पष्ट और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए। क्लेम प्रक्रिया पारदर्शी हो – ताकि अस्पताल को भुगतान समय पर मिले, और मरीज को राहत।

इसके साथ ही गैर-पंजीकृत अस्पतालों को भी स्थिति स्थिरीकरण का अधिकार और भुगतान की गारंटी दी जाए। इससे जीवन रक्षा का अवसर बढ़ेगा।

अंततः -जागरूकता। जनता को पता होना चाहिए कि सड़क पर पड़ी हर जान, एक योजना से जुड़ी हुई है। पोस्टरों से लेकर मोबाइल संदेश तक, स्कूलों से लेकर पंचायतों तक-हर जगह इस योजना की जानकारी दी जानी चाहिए। क्योंकि जब जनता को पता होगा,तभी अस्पताल जवाबदेह होंगे। यह नकदरहित उपचार योजना, अगर सही मायनों में लागू हो जाए, तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

लेकिन जब तक यह योजना कागजी ही बनी रहती है, तब तक यह एक और 'योजना' बनकर रह जाएगी–जो स्लोगन में चमकेगी, लेकिन सड़क पर बहे खून से बेखबर रहेगी। इस देश की सड़कों पर खून बहता है-और व्यवस्था पोर्टल लोड होने का इंतजार करती है।

मीडिया की विश्वसनीयता पर उठते सवाल

आकाशवाणी का यह वह जमाना था जब टेलीप्रिंटर और टेलीफोन ही प्रमुख माध्यम होते थे। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से समाचारों की डाक आती थी वहीं प्रादेशिक समाचारों में समूचे प्रदेष के प्रमुख समाचारों का समावेश महत्वपूर्ण होता था।

संजय बैंसला

मीडिया की विश्वसनीयता पर उठते सवालों के बीच आकाशवाणी और बाद में दूरदर्शन के शुरूआती वे दिन बरवस याद आ जाते हैं जब आकाशवाणी के नेशनल और प्रादेशिक समाचारों के प्रति आमजन के विश्वास को इसी से समझा जा सकता है कि चौराहों की चाय-पान की दुकानों पर खड़े होकर भी समाचार सुनने में किसीको कोई संकोच ना होकर गर्व महसूस होता था। आकाशवाणी के नेशनल समाचारों की बात हो तो सुबह 8 बजे और रातः पौने नो बजे के समाचार बुलेटिनों की बेसब्री से प्रतीक्षा होती थी तो प्रातःकालीन प्रादेशिक समाचार के साथ ही खासतौर से सायंकालीन सात बजे के प्रादेशिक समाचार को कोई भी प्रदेषवासी मिस नहीं करना चाहता था। आकाशवाणी और दूरदर्शन का यह स्वर्णकाल इस मायने में कहा जा सकता है कि सरकारी नियंत्रण में होने के बावजूद आमआदमी तो क्या पक्ष और विपक्ष के नेतागण भी समाचारों की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं उठा पाते थे। होता तो यहां तक था कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों से लोग अपनी घड़ियों को मिलाया करते थे। विश्वसनीयता का यह कोई आसान काम नहीं था पर उस समय के दिग्गज मीडियाकर्मियों ने अपनी मेहनत, लगन और निष्पक्षता से सींचने का काम किया और उसका परिणाम यह रहा कि उस समय के मीडिया दिग्गजों को समूचे समाज में चाहे वह राजनीतिक स्तर हो, ब्यूरोक्रेटिक स्तर हो या फिर आमजन सभी जगह सम्मान से देखा जाता था। यदि प्रादेशिक स्तर की बात की जाए तो आकाशवाणी जयपुर अजमेर के समाचार संपादक और बादमें दूरदर्शन जयपुर केन्द्र के समाचार एकांश के निदेशक मोहनराज सिंघवी जिन्हे मीडिया जगत में एमआर सिंघवी के नाम से जाना जाता रहा है की मेहनत, निष्पक्षता और मीडिया की स्वतंत्रता की पक्षधरता का ही परिणाम रहा कि मीडिया जगत में एमआर सिंघवी एक ब्राण्ड के नाम से पहचान बनाने में कामयाब रहे। पक्ष-विपक्ष के सभी नेता, समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों सहित आमजन में जिस तरह की छवि एमआर सिंघवी की बनी वह आजके मीडिया कर्मियों के लिए ईर्च्छा का कारण बन सकती है तो प्रेरणास्पद भी है। बात में इतना दम की क्या तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीमण्डल के सदस्यगण और क्या ब्यूरोक्रेसी के कर्ताधर्ता एमआर सिंघवी की बात को कमतर समझने की भूल भी नहीं कर सकते थे।

यह आज के समय में अविश्वसनीय कल्पना ही हो सकती है कि 90 के दशक में एमआर सिंघवी के आकाशवाणी जयपुर पिंकसिटी पेट्रोलपंप के पास स्थित आवास पर मिलनेवाले जरुरतमंद लोगों का जमावड़ा इस तरह से लगा रहता था जैसे किसी राजनेता के निवास पर लगा होता था। पीड़ित व्यक्ति के लिए एमआर सिंघवी एक सहारा रहे हैं। इसका कारण भी यह रहा कि यदि काम जायज है और हितकारक है तो सिंघवी जी आने वाले व्यक्ति के सामने ही संबंधित मंत्री से लेकर अधिकारी को फोन करने में किसी तरह का संकोच नहीं करते थे और आने वाले व्यक्ति की आंखें एहसान से बोझिल हो जाती तो काम भी आसानी से हो जाता था। खासबात यह कि बिना जानपहचान भी कोई अपने दुखदर्द को लेकर पहुंच जाता था तो सहयोग करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ते। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं। किसी दिन आकाशवाणी के अनुबंध पर समाचार अनुभाग के लिए लिखित परीक्षा हुई और एक दिन एकाएक घर पर आकाशवाणी से अनुबंध का पत्र आ गया। डिप्लोमा भले ही पत्रकारिता में कर लिया हो पर अनुभव के मामलें में शून्य होने के बावजूद जिस तरह से सिंघवी जी ने मेरे जैसे को तराशा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मजे की बात यह कि एमआर सिंघवी पोलियों से ग्रसित होने के कारण चलने फिरने में असुविधा के बावजूद किसी

के भी सहयोग के लिए उनके साथ जाने को तैयार हो जाते। विकलांगों के लिए उन्होंने संघर्ष करने के साथ ही स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के खेलों का आयोजन, संयोजन व प्रोत्साहन दिया। देवेन्द्र झाझड़िया तो एक उदाहरण मात्र है जिन्हें विश्वपटल पर पहचान सिंघवी जी की प्रेरणा-प्रोत्साहन और सहयोग से ही संभव हो सका।

आकाशवाणी का यह वह जमाना था जब टेलीप्रिंटर और टेलीफोन ही प्रमुख माध्यम होते थे। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से समाचारों की डाक आती थी वहीं प्रादेशिक समाचारों में समूचे प्रदेष के प्रमुख समाचारों का समावेश महत्वपूर्ण होता था। ऐसे में लगभग प्रतिदिन समाचार संपादक होने के बावजूद बिना किसी संकोच के फोन से समाचार लेने व स्वयं लिखने तक में संकोच नहीं करने के कारण ही मीडिया जगत में पहचान और विश्वसनीयता बनी। बुलेटिन में खबरों के चयन से लेकर प्रसारण तक तनावरहित वातावरण में काम करना और नए लोगों को प्रोत्साहित करना यही तो सिंघवी जी की पहचान रही। हिम्मत यह कि जयपुर दूरदर्शन निदेशक समाचार रहते हुए तत्कालीन केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्व. गिरिजा व्यास के जयपुर में एक ब्यूटीपार्लर के उद्घाटन के समाचार प्रसारित करने के दबाव के बावजूद मीडिया मानदंडों के विरुद्ध बताते हुए प्रसारित नहीं करना सिंघवी जैसे बिड़ला ही कर सकते हैं। इसी तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाडिया के पिताजी के देहावसन के समाचार प्रसारण के लिए लाख दबाव के बावजूद विनम्रता से नीति विरुद्ध जाकर समाचार प्रसारित नहीं करने का निर्णय कोई सिंघवी जैसा ही ले सकता है। आज तो केन्द्रीय मंत्री वो भी स्वयं का माईबाप यानी कि स्वयं के विभाग का हो तो उसकी खबर तो क्या आगे पीछे सेवा सुश्रुषा में ही लगे रहने में गर्व महसूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एमआर सिंघवी कोई ऐसे ही नहीं बनता, कोई ऐसे ही राजनेताओं, पक्ष विपक्ष के छोटे से लेकर बड़े नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स सभी के लिए सम्मानजनक अपनी कार्यशैली, निष्पक्षता, निष्ठा और मेहनत से ही बना पाता है। प्रदेश का संभवतः कोई छोटा-बड़ा नेता या अधिकारी ऐसा नहीं होगा जो एमआर सिंघवी के नाम, पहचान और उनकी कार्यशैली का कायल नहीं होगा। इतने विस्तृत केनवास पर पहचान और विश्वसनीयता कोई ऐसे नहीं बन जाती बल्कि यह ईमानदारी, निस्वार्थता और सहायता और सहयोग की भावना के कारण ही हो पाता है। यही सिंघवी जी की पूंजी मानी जा सकती है। समाचार में समाचारत्व है तो उसे बिना किसी पक्षपात के स्थान मिलता वहीं तत्कालीन राज्यपाल जोगेन्द्र सिंह द्वारा रिकार्ड वाइस ओवर प्रसारित कराने के दबाव के बावजूद स्तरीय नहीं होने से प्रसारित नहीं करने का साहस कोई एमआर सिंघवी ही कर सकता है। यह सब इसलिए कि आज मीडिया की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। खासतौर से इलेक्ट्रोनिक चैनलों की विश्वसनीयता पूरी तरह से दाव पर लग चुकी है। चैनलों पर बेसिरफेर की चर्चा और आरोप-प्रत्यारोप का मंच बनना आज आम हो गया है। रही सही कसर सोशियल मीडिया ने कर दी है जहां अपलोड सामग्री भ्रम पैदा करने का काम करने के साथ ही उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ी कर देती है यही कारण है कि चैनलों पर समाचार प्रसारित होते समय वीडियो की विश्वसनीयता पर स्वयं चैनल द्वारा सवाल खड़े किया जाना आम है। होना तो यह चाहिए कि जब तक समाचार संपादक स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक केवल टीआरपी के चक्कर में ऐसे समाचार व वीडियो को प्रसारित ही नहीं करना चाहिएं। क्योंकि यह सवाल दर्शकों के विश्वास को बनाए रखने का हो जाता है। एक समय था जब कोई भी बड़ी घटना हो जाती थी तो लोग आकाशवाणी के आगामी समाचार बुलेटिन पर कान लगाकर पुष्टि होने पर ही विश्वास करते थे। आज अपुष्ट समाचार आम होते जा रहे हैं। आकाशवाणी के पुराने दिनों और एमआर सिंघवी जैसे व्यक्तित्व व संपादकों के बहाने आज मीडिया की विश्वसनीयता का वहीं पुराना युग देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रसारित समाचार की विश्वसनीयता पर कोई सवाल उठता है तो फिर यह मीडिया के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होना चाहिए। मीडिया जगत को आज एमआर सिंघवी जैसे मीडिया दिग्गज की आवश्यकता महसूस हो रही है ताकि मीडिया चाहे इलेक्ट्रोनिक हो या प्रिंट उस पर प्रसारित या प्रकाशित समाचार को वेदवाक्य की तरह विश्वसनीय माना जाए। बदलते हालात में आज यह आवश्यकता अधिक हो गई है क्योंकि समाज आज भ्रमित अधिक हो रहा है तो मीडिया और सोशियल मीडिया ने विश्वसनीयता को ही प्रष्नों के घेरे में खड़ा कर दिया है। समाचार पर प्रश्न उठने की कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए।

भारतीय संसदीय इतिहास के काले अध्याय के 50 साल

25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी।

यह किसी देश के संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को असाधारण स्थितियों, जैसे युद्ध, विद्रोह या अन्य संकटों, जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता तथा भारत के लोकतंत्र के लिये खतरा पैदा करते हैं, पर त्वरित एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है।

50 साल पहले क्या थी परिस्थितियां

मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के चार साल बाद राज नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किय। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुईं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है।

संसद में भारी बहुमत की सरकार रही

1967 और 1971 के बीच, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय, प्रधानमंत्री के सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया।

उच्च न्यायालय द्वारा 6 साल के लिए बेदखल

12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और छह साल के

लिए पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए लेकिन आदतन श्रीमती गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया। राज नारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी जी के अपील पर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दी ।1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिखी। यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर छह वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

25 जून 1975 को आपातकाल घोषित

इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 25 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई।

21 महीने रहा ये काला आपात काल

25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी।

आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता था

38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975: इसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया।

प्रेस पर सेंसरशिप

1975 के आपातकाल के दौरान, सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया, और जबरन नसबंदी जैसे कई मनमाने फैसले लिए। सरकार ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लगा दी, जिससे वे सरकार की आलोचना नहीं कर पा रहे थे।

गिरफ्तारियां

सरकार ने राजनीतिक विरोधियों, कार्यकताओं और पत्रकारों को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया, और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। यह भारत के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है।

जबरन नसबंदी

1976 में, संजय गांधी के नेतृत्व में, सरकार ने बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया, जिसमें लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया। इस पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा देश की आबादी को नियंत्रित करना था। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराई गयी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संजय गांधी की भूमिका की सटीक सीमा विवादित है। रुखसाना सुल्ताना एक समाजवादी थीं जो संजय गांधी के करीबी सहयोगियों में से एक होने के लिए जानी जाती थींऔर उन्हें पुरानी दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्रों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान के नेतृत्व में बहुत कुख्याति मिली थी।

संविधान का दुरुपयोग

आपातकाल लगाने के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, जिससे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जिससे सरकार को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की अनुमति मिल गई।

मीसा और डीआईआर का दुरुपयोग

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) और रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम (डीआईआर) जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया गया ताकि लोगों को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें हिरासत में रखा जा सके।

लोकतंत्र का दमन

आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया और सरकार की आलोचना करने वाली आवाजें दबा दी गईं। आपातकाल के दौरान हुई इन मनमानीयों के कारण, इसे भारत के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है।

राम मंदिर के स्वर्ण शिखर की आभा से आलोकित हुआ राष्ट्र

मुकुल शर्मा

मुख्य मंदिर यानी अपनी जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर के भूतल में कोटि-कोटि भक्तों के आराध्य रामलला तो पहले से ही प्रतिष्ठित हैं, अब आगामी पांच जून को इसी मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के साथ परकोटे के बाकी 6 मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है।

आयोध्या में राम मंदिर संपूर्ण विश्व में रचने–बसने वाले सनातनियों की शताब्दियों की प्रतीक्षा, संयम, धैर्य, अनुशासन और आस्था का प्रतीक है। यह राम नहीं, राष्ट्र मंदिर है। विरोधी भले ही सनातन और राम मंदिर का विरोध करते रहें लेकिन करोड़ों सनातनियों के हृदय में उनके आराध्य भगवान श्रीराम रचते–बसते हैं। भगवान राम के मंदिर को वह अपना पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं।

मुख्य मंदिर यानी अपनी जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर के भूतल में कोटि-कोटि भक्तों के आराध्य रामलला तो पहले से ही प्रतिष्ठित हैं, अब आगामी पांच जून को इसी मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के साथ परकोटे के बाकी 6 मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इनमें गणेश, भगवान शिव, देवी भगवती, हनुमान जी, भगवान सूर्य, देवी अन्नपूर्णा और शेष अवतार के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह आयोजन अयोध्या के धार्मिक इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रहा है। त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 5 जून को गंगा दशहरा के पावन पर्व के दिन पूणार्हुति के साथ संपन्न होगा। श्रीराम दरबार प्रतिष्ठित होने के साथ रामलाल से राजाराम तक की यात्रा पूर्ण होगी। इसी बीच राम जन्मभूमि मंदिर के शिखरों पर सोने की परत चढ़ाने का कार्य हो रहा है। यह कार्य मंदिर की भव्यता में चार चांद लगाएगा।

राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है, राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्वर्णिम और ऐतिहासिक अवसर सनातनधर्मियों को कड़े संघर्ष से प्राप्त हुआ है, जिसका 550 सालों से अधिक का इतिहास है। इसमें 70 से अधिक बार का संघर्ष, जिसमें से अधिकतर मुगल आक्रांताओं द्वारा भारतवासियों और हमारे मंदिरों पर हमले का रक्तरंजित इतिहास शामिल है। अनगिनत आन्दोलनों के बाद अंततः 22 जनवरी 2024 के दिन हिन्दू समाज को अपने आराध्य प्रभु श्रीराम को जन्म भूमि पर निर्मित भव्य मंदिर में पुनर्स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान बनकर मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। यह दिन भारत की आस्था, अस्मिता, स्वाभिमान और गौरव की पुनर्स्थापना का दिन के तौर पर अंकित है।

अयोध्या में प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का योगदान स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मठ के महंत हैं, उसी से अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की शुरूआत हुई थी। योगी जी के गुरु महंत अवेद्यनाथ 12 सितंबर 2014 को ब्रह्मलीन हुए। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ के पास मंदिर आंदोलन के दौरान दो सबसे अधिक अहम पदों राम जन्म भूमि यज्ञ समिति और राम जन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष था। ये दायित्व इस बात का प्रमाण है कि आजादी के आंदोलन के बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाले राम मंदिर आंदोलन में उनका क्या कद था? महंत अवैद्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ थे। योगी आदित्यनाथ भी इस आंदोलन को मुखरता प्रदान करते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि 'राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं...मेरे लिए जीवन का मिशन है'। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर परिसर में उपस्थित रहेंगे। विशेष बात यह है कि 5 जून को मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है।

हिन्दू बहुल देश में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली को मुक्त करवाने में जिस तरह के अवरोध उत्पन्न किए गए वे अकल्पनीय हैं। यदि सोमनाथ के साथ ही राम जन्मभूमि का मसला भी तत्कालीन नेहरू सरकार सुलझा लेती तब शायद इसे लेकर राजनीति करने का किसी को अवसर नहीं मिलता। लेकिन आजादी से लेकर आजतक कांग्रेस ने राम के नाम पर घिनौनी राजनीति का प्रदर्शन किया है। एक ऐसी राजनीति जिसने राम मंदिर मुद्दे को उलझाने का काम किया। वर्ष 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु को तोड़ कर तय वर्तमान मार्ग से ही लागू किये जाने पर जोर देते हुए कहा था कि भगवान राम के अस्तित्व में होने के बारे में कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। ये भी कहा था कि रामायण महज कल्पित कथा है। वर्तमान में, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के कई नेता राम मंदिर और सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयानबाजी करने से बाज नहीं आते।

स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था कि, राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा है। उनका वह वक्तव्य सही मायने में एक संदेश था जिसमें राजनीति नहीं थी। सही बात तो ये है कि राम मंदिर का विरोध करने वालों ने ही इसे वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बना दिया। कांग्रेस और अन्य कुछ दल मुस्लिम मतों के कारण इस मुद्दे पर हिंदुओं के न्यायोचित दावों की अनदेखी करते रहे। प्रतिक्रिया स्वरूप इस मामले ने दूसरा मोड़ ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की बहुसंख्यक आबादी के आराध्य श्रीराम की जन्मभूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने का कार्य न्यायालय के निर्णय से संभव हो सका। और वह प्रक्रिया भी वर्षों नहीं दशकों तक चली। सबसे बड़ी बात ये हुई कि बाबरी ढांचे की तरफदारी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता के झंडाबरदार बने हिन्दू नेतागण भी करते रहे।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि, शताब्दियों का संघर्ष अब अयोध्या में प्रत्यक्ष साकार रूप में फलीभूत होता दर्शित हो रहा है। भारत के कण-कण में राम हैं। राम मंदिर में राम दरबार के साथ परकोटे के बाकी 6 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की सुप्त आत्मा को जागृत करने का काम करेगी। राम मंदिर के निर्माण से सशक्त राष्ट्र का निर्माण होने वाला है। भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है। यह वास्तव में भारत की सुप्त आत्मा है। यही भारत को दुनिया के अंदर सर्वशक्तिशाली बनायेगी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो रामभक्ति है वहीं राष्ट्रभक्ति है। राजनीति तोड़ने का कार्य करती है, धर्म जोड़ता है। राम मंदिर ने देश को जोड़ दिया है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिन्दूर में हमारे सैनिकों ने जिस पराक्रम का प्रदर्शन किया है उससे न केवल शत्रु बल्कि पूरी दुनिया अचम्भित है। ये बढ़ते हुए सशक्त भारत की एक झलक मात्र है।

राष्ट्रीय अस्मिता और अखण्डता भी अयोध्या से जुड़ी है। श्रीराम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का प्रश्न नहीं है, इसके साथ भावी सामाजिक संरचना की संकल्पना भी जुड़ी है। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण, कालसापेक्ष किन्तु कालातीत दर्शन और दृष्टि का सृजन बीज राम मंदिर निर्माण और उसकी भव्यता में निहित है। राम मंदिर का दूसरा पहलू राष्ट्र मंदिर के रूप में स्थापित है और इस भावना के अनुरूप यह परिसर आस्था के साथ राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय एकता और समाज निर्माण के प्रति भी महनीय भूमिका का निर्वहन करने को तैयार है।

विश्वभर में रचने और बसने वाले हिन्दू धर्मावलम्बी राम मंदिर की दूसरी प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 जून की तिथि विश्व इतिहास में सदा के लिए अमर रहेगी। श्रीराम मंदिर के शिखर की स्वर्णिम आभा से सम्पूर्ण विश्व में सुख, समृद्धि, शांति, सद्भावना और सहिष्णुता का प्रकाश फैले और भारत फिर एक बार विश्व गुरु के तौर पर स्थापित हो, यही कामना है।

डिजिटल क्रांति की कथा सुनाने लगे गांव

भारत के दूरसंचार और इंटरनेट उपयोग में पिछले 11 वर्षों में आई क्रांति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रति उपयोगकर्ता डाटा खपत 2014 में जहां 61 एमबी हुआ करती थी, आज 2025 में 21.5 जीबी हो चुकी है।

एन के शर्मा

आज गलवान और सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में तैनात हमारे सैनिक इंटरनेट की तेज स्पीड के साथ पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं। जो कभी बर्फीली खामोशियों में रहते थे, वे अब हाई-स्पीड इंटरनेट से संवाद कर रहे हैं। देश के पूर्वोत्तर का व्यापारी वैश्विक बाजार तक पहुंच रहा है, तो छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई से अपने सपनों को ऊंची उड़ान दे रहे हैं। यह सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, मनोबल बढ़ाने वाली क्रांति है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, यह उस संकल्प की परिणति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' के रूप में लिया था। बीते 11 वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों ने एक नई डिजिटल क्रांति को जन्म दिया, जो न केवल शहरों को, बल्कि गांवों, सीमाओं व जंगलों को भी जोड़ रही है। आज, जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, तो इस यात्रा में मजबूत दूरसंचार तंत्र व भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी एक सशक्त उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने सिर्फ तकनीकी विकास नहीं, बल्कि तकनीक के माध्यम से जन-सशक्तीकरण का नया अध्याय रचा है।

भारत के दूरसंचार और इंटरनेट उपयोग में पिछले 11 वर्षों में आई क्रांति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रति उपयोगकर्ता डाटा खपत 2014 में जहां 61 एमबी हुआ करती थी, आज 2025 में 21.5 जीबी हो चुकी है। मेगाबाइट से गीगाबाइट तक की यह वृद्धि 'डिजिटल इंडिया' की नींव बन रही है। मात्र 11 साल में ब्रॉडबैंड कनेक्शन में 1,449 फीसदी की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी संख्या आज 95 करोड़ है। मार्च 2014 से मार्च 2025 तक भारत में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या 93.3 करोड़ से बढ़कर 120.167 करोड़ हो गई है, जिसमें मोबाइल उपयोगकताओं की संख्या 115.786 करोड़ है। आज भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निमार्ता बन चुका है। यहां बिकने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल देश में ही बनते हैं। एक समय था, जब एक जीबी डाटा के लिए उपभोक्ताओं को 268.97 रुपये चुकाने पड़ते थे, लेकिन आज वह मात्र 9.34 रुपये में उपलब्ध है, यानी 96 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट हमारे 'सर्वव्यापी कनेक्टिविटी' को शक्ति दे रही है।

ग्यारह साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली, तब भारत के लाखों गांव इंटरनेट कनेक्टिविटी से अछूते थे। प्रधानमंत्री जानते थे कि यदि भारत को 21वीं सदी में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभानी है, तो प्रत्येक गांव, पंचायत और कस्बे को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना होगा। इसी दृष्टि से 'भारत नेट परियोजना' शुरू की गई, जो विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण टेलीकॉम कनेक्टिविटी परियोजना है। इसके पहले चरण में 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है, अगले चरण में और 2.64 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। इन

उपलब्धियों से भारत में एक विशाल डिजिटल हाईवे का निर्माण हुआ है, जिसके लाभ आज देश के हर कोने में महसूस किए जा रहे हैं।

दूरसंचार का महत्व केवल फोन, टीवी या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन का एक सशक्त उपकरण बन चुका है। जन-धन, आधार और मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी ने डिजिटल वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज इसी डिजिटल हाईवे के माध्यम से भारत वैश्विक डिजिटल पेमेंट्स में 46 प्रतिशत योगदान दे रहा है, जो देश की तकनीकी क्षमताओं और जन-सहभागिता का सशक्त प्रमाण है।

ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के अनुरूप इस सरकार ने लगातार तकनीकी नवाचार करते हुए देश की इंटरनेट कनेक्टिविटी को आधुनिक व सक्षम बनाए रखा है। इस प्रयास के केंद्र में है हमारा स्वदेशी संचार नायक- बीएसएनएल। 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप यह एक बार फिर मजबूती से उभर रहा है। 17 वर्षों में पहली बार इसने लगातार दो वित्तीय तिमाही में शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

देश भर में 93,000 से अधिक 4जी टावर की स्थापना के साथ बीएसएनएल अपने उपयोगकताओं को सुलभ और निर्बाध 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहा है, वह भी पूर्ण स्वदेशी तकनीक के माध्यम से।

बीएसएनएल ने महज 22 महीनों में देश का पहला पूर्ण स्वदेशी 4जी स्टैक विकसित किया, जिससे भारत उन पांच देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो यह तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके हैं। जनता के इस भरोसे और समर्थन ने बीएसएनएल को यह ऐतिहासिक सफलता दिलाई है, जो ह्यडिजिटल इंडियाह्ल के आत्मनिर्भर संचार तंत्र की एक बड़ी उपलब्धि है।

इसी संचार क्रांति की अगली कड़ी में अब डाक विभाग भी तकनीक और सेवा के क्षेत्र में एक नई भूमिका निभा रहा है। एक समय था, जब डाक विभाग को केवल पत्र लाने-ले जाने तक सीमित माना जाता था, पर आज यह विभाग ग्रामीण भारत की जीवन-रेखा के रूप में उभर रहा है। 1.6 लाख से अधिक डाकघरों के व्यापक नेटवर्क के साथ इसे एक सशक्त लॉजिस्टिक्स और सेवा प्रदाता संगठन के रूप में बदला जा रहा है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं अब देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी हैं। यह बदलाव इतना व्यापक है कि अब 'डाकिया डाक लाया' की पारंपरिक छवि की जगह 'डाकिया बैंक लाया' की नई पहचान ने ले ली है। यह परिवर्तन सिर्फ सेवा का नहीं, बल्कि सशक्तीकरण का माध्यम बन गया है, जहां ग्रामीण भारत को अब शहरों की ओर देखने की जरूरत नहीं, बल्कि गांव अब डिजिटल भारत की गति को संबल दे रहे हैं। सरकार डाक विभाग को देश की आर्थिक आधारशिला का हिस्सा बनाते हुए इसे एक वित्तीय महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

ग्रामीण विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का ही यह परिणाम है कि गांव में बैठे-बैठे आम जनता सुविधाजनक तरीके से न सिर्फ सरकारी सुविधाओं का लाभ ले पा रही है, बल्कि राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अब बड़े शहरों पर आश्रित नहीं होना पड़ता, क्योंकि उनके गांव में सुलभ मजबूत कनेक्टिविटी और ऑनलाइन कक्षाएं उनके लिए नित नए द्वार खोल रही हैं। व्यापारियों को अब बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से सभी लेन-देन और हिसाब ऑनलाइन ही हो जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश को डिजिटल कनेक्टिविटी में विश्व-स्तरीय सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध रही है और पिछले 11 वर्ष इसकी अभूतपूर्व सफलता के गवाह रहे हैं।

2026 के पंचायत चुनाव में छिपा है 2027 का जनादेश

सचिन तोमर

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सबसे अहम सियासी इम्तिहान पंचायत चुनाव होगा, जिसे सूबे की सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इन चुनावों की तैयारी ने अभी से पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से साफ हो गया है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या अब 57,695 रह गई है। वर्ष 2021 में ये संख्या 58,199 थी, यानी इस बार 504 पंचायतें कम हो गई हैं। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रदेश में तेजी से हुए शहरीकरण को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शहरी सीमाओं के विस्तार के चलते कई ग्राम पंचायतें अब नगर निकायों में शामिल हो गई हैं। इससे कई जिलों में पंचायतों की संख्या घट गई है। देवरिया में सबसे अधिक 64 ग्राम पंचायतों का विलय हुआ है, इसके बाद आजमगढ़ में 47, प्रतापगढ़ में 45, अमरोहा और गोरखपुर में 21-21 पंचायतें कम हुई हैं। गाजियाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर जैसे अन्य जिलों में भी यही स्थिति देखने को मिली है।

पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना के अनुसार पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में कराए जाने की संभावना है। इस बार 57,695 ग्राम प्रधान, 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। यह चुनाव न केवल ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करेंगे, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों का जनाधार भी तय करेंगे। यही कारण है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी इस बार सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, तो वहीं विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस चुनाव को 2027 की लड़ाई की बुनियाद मान रही है।

सबसे बड़ी बहस इस समय पंचायत चुनावों में सुधार को लेकर हो रही है। कई दलों की मांग है कि अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी सीधे जनता से कराए जाएं, जैसे ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है। अभी तक यह चुनाव पंचायत समिति या जिला पंचायत सदस्यों द्वारा होता आया है, जिससे भारी भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और एनडीए के भीतर से भी ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता इन पदों पर डायरेक्ट इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और संभवतः इसे लागू करने के लिए विधानमंडल में प्रस्ताव लाया जा सकता है।

राजनीतिक तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा इन चुनावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दुरुपयोग

कर रही है। अखिलेश का कहना है कि भाजपा सीसीटीवी और डेटा एनालिटिक्स के जरिए मतदाताओं की निगरानी कर रही है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जो लोग सीसीटीवी में पकड़े जा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा के भरोसे लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती क्योंकि उसका उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहना है, चाहे इसके लिए कितनी भी अनैतिक तकनीक और रणनीति क्यों न अपनानी पड़े।

अखिलेश यादव ने अपनी PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नीति को भी आगे बढ़ाते हुए पंचायत चुनाव में सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्रमुख बनाया है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन एक 'भावनात्मक गठबंधन' है, जो उन सभी के लिए है जो समाज में हाशिए पर हैं। उन्होंने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय का आधार बताया और कहा कि सपा इसके पूर्ण समर्थन में है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह चेतावनी भी दी कि जनगणना के आंकड़ों में किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वहीं भाजपा भी पंचायत चुनाव को लेकर बेहद सतर्क है। वह जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए डइउ वर्ग के बीच कैम्पेन चला रही है। भाजपा यह बताने की कोशिश कर रही है कि पिछली सरकारों ने मंडल आयोग और काका कलेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू न करके पिछड़ों के साथ अन्याय किया। भाजपा अब इस वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए जातीय जागरूकता अभियान चला रही है और पंचायत चुनाव के जरिए इस समर्थन को मजबूती देने की तैयारी में है।

पंचायत चुनावों की तैयारी के बीच कांग्रेस का रुख भी साफ हो चुका है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह इन चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहेगी और 'INDIA' ब्लॉक की भावना के अनुरूप सभी क्षेत्रीय दलों के साथ समन्वय बनाकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने यहां तक कहा कि अगला चुनाव केवल भाजपा के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि यह चुनाव आयोग और संपूर्ण चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता की लड़ाई भी होगा। उन्होंने पंचायत चुनाव में अकऔर डाटा निगरानी जैसे प्रयोगों पर चिंता जताई और कहा कि इससे लोकतंत्र को गंभीर खतरा है।

पंचायत चुनावों के समानांतर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्राथमिक स्कूलों की जमीन बेचने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इंटरमीडिएट कॉलेजों की हालत खराब है, और सरकार की निगाह केवल उनकी जमीनों पर है। यह टिप्पणी ग्रामीण मतदाताओं को सीधे संबोधित करती है, जिनके बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके अलावा, अखिलेश ने बदायूं में पटेल समाज के साथ हुए कथित अन्याय का मुद्दा भी जोरशोर से उठाया है। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि समाजवादी पार्टी इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश और विदेश भेजे गए मजदूरों के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और पूछा कि ऐसे मामलों में आज तक किसी मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ।

इन तमाम राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों, नीतिगत परिवर्तनों और तकनीकी प्रयोगों के बीच पंचायत चुनाव अब केवल स्थानीय निकाय का चुनाव न होकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला यथार्थ बन चुका है। यह चुनाव सामाजिक न्याय, प्रशासनिक पारदर्शिता, डिजिटल नैतिकता और राजनीतिक गठबंधन की परिपक्वता की असली परीक्षा होगी। 2026 में होने वाला यह चुनाव चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, लेकिन इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव तक गूंजता रहेगा। यही वजह है कि सभी दल अभी से अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं और इस बार पंचायत चुनाव महज ग्राम प्रधानों का नहीं, बल्कि प्रदेश की सियासी दिशा का जनादेश बनता नजर आ रहा है।

आखिर अमेरिका, चीन और रूस के 'साम्राज्यवादी लव ट्रेंगल' को क्यों खटकता है भारत ?

अरब और यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए भारत ने रूस का सहयोग लिया और इस विशाल भूभाग पर अमेरिका और चीन दोनों को कूटनीतिक पटखनी देने का जो निश्चय किया है, उससे देर-सबेर दिल्ली-मास्को एक्सप्रेस वे की आधारशिला तैयार हो जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की शतरंजी विसात पर भारत ने अमेरिका को जो पटखनी दर पटखनी दी है, उसकी खुन्नस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर साफ महसूस की जा सकती है। वहीं, भारत के सम्बन्ध में उनकी बदलती नीतियों से अब यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि रूस और भारत के संयुक्त चक्रब्यूह में निरंतर फंसते जा रहे अमेरिका के पास अब चीन के समक्ष घुटने टेकने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा है। लेकिन आप यह जानकर और भी हैरत में पड़ जाएंगे कि इसके बाद भी अमेरिका

अवकाश शर्मा

की दुश्वारियां कम नहीं होने वाली हैं। ऐसा इसलिए की तेजी से वैश्विक महाशक्ति बनते जा रहे भारत ने अंतरराष्ट्रीय दुनियादारी में अमेरिका, चीन और रूस तथा इनके शागिर्द देशों/गठबंधन भागीदारों को साधते हुए खुद को आगे बढ़ाने का जो निश्चय किया है, उससे अमेरिका और चीन के होश फाख्ता हो चुके हैं।

वहीं, भारत का सदाबहार दोस्त रूस मन ही मन गदगद है, क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ जो चक्रब्यूह 15 देशों का समूह सोवियत संघ या उसका बचा हुआ सर्वाधिक शक्तिशाली धड़ा रूस आज तक नहीं रच पाया, उसे भारत ने महाभारत कालीन चक्रब्यूह विधा की तर्ज पर ऐसा रचा की, उसमें फंसकर अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों चिग्घाड़ मार मार कर बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहे हैं।

इधर, भारत के लिए परेशानियों का सबब बनते जा रहे चीन के खिलाफ भी भारत ने ऐसा चक्रब्युह रचा है कि देर सबेर उसमें उलझकर वह बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए भारत ताइवान, तिब्बत और उन मध्य एशियाई देशों जो सोवियत संघ से जुड़े थे, के साथ समझदारी भरे आतंकवाद विरोधी रिश्ते प्रगाढ़ कर रहा है।

उधर, अरब और यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए भारत ने रूस का सहयोग लिया और इस विशाल भूभाग पर अमेरिका और चीन दोनों को कूटनीतिक पटखनी देने का जो निश्चय किया है, उससे देर-सबेर दिल्ली-मास्को एक्सप्रेस वे की आधारशिला तैयार हो जाएगी।

इधर, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी भारत अपनी स्थिति निरंतर मजबूत बना रहा है। अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा को भी वह देर सबेर काबू में कर लेगा, क्योंकि वहां पर पंजाबी लॉबी काफी मजबूत है।

ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, चीन और रूस के बीच पूरी दुनिया को साम्राज्यवादी लिहाज से बांटने की जो डील करने वाले हैं, उसकी तैयारी में भारत सबसे बड़ा बाधक बन रहा है। जबकि कारोबारी से राष्ट्रपति बने ट्रंप ने अपनी योजनात्मक किताब में तीनों महाशक्तियों के बीच 3 ही पावर सेंटर्स होने की बात कही है और इसमें भारत के लिए कोई जगह नहीं है।

इस क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शायद यह भूल रहे हैं कि जिस ग्रेट ब्रिटेन से उन्होंने दुनिया की बादशाहत मिलकर छीनी है, अब वही यूरोपीय संघ की आड़ में अपना पुराना हिसाब किताब अमेरिका से चुकता करेगा। उसके इस मिशन में फ्रांस और इटली भी उसका साथ देंगे।

इधर, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य खलनायक रहा जर्मनी एक बार फिर रूस के खिलाफ मुखर होकर तीसरा विश्व युद्ध करवाने पर आमादा है। वहीं रूस के सहयोगी चीन, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देश आपसी समझदारी से जो कुछ कर रहे है, उससे अरब का संघर्षभूमि बनना स्वाभाविक है। इसके बाद अमेरिका के सहयोगी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, सऊदी अरब की भी परेशानी बढ़ेगी।

देखा जाए तो साम्राज्यवादी नजरिए से अमेरिका-चीन-रूस, रूस-चीन-अमेरिका, चीन-रूस-अमेरिका के अलावा समय समय पर रूस-चीन-भारत, अमेरिका-चीन-भारत, अमेरिका-रूस-भारत आदि के जो साम्राज्यवादी चक्रब्यूह तैयार किये गए, उसमें से किसी में भारत नहीं फंसा। क्योंकि कुल मिलाकर भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जो गुटनिरपेक्ष है। उसका दोस्त रूस भी उसकी गुटनिरपेक्षता में मददगार साबित हुआ है। ऐसे में चाहे अमेरिका-यूरोप गठबंधन हो या रूसी यूरेशिया-चीन-अरब गठबंधन, इनके बीच महायुद्ध होना स्वाभाविक है। ऐसे में गुटनिरपेक्ष भारत का महत्व बढ़ेगा।

वहीं भारत ने रणनीतिक लिहाज से रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका संरक्षित इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध से दूरी बनाकर रखी है। वह चीन-ताइवान युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहा है। इसी बीच अमेरिका-चीन ने भारत को पाकिस्तान से भिड़ाने की जो साजिश रची, उसको भी भारत ने अपने पक्ष में मोड़ लिया। इससे अमेरिका-चीन की जहां कलई खुली, वहीं रूस के साथ हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ हुए।

भारत का सदाबहार दोस्त रूस मन ही मन गदगद है, क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ जो चक्रब्यूह 15 देशों का समूह सोवियत संघ या उसका बचा हुआ सर्वाधिक शक्तिशाली धड़ा रूस आज तक नहीं रच पाया, उसे भारत ने महाभारत कालीन चक्रब्यूह विधा की तर्ज पर ऐसा रचा की, उसमें फंसकर अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों चिग्घाड़ मार मार कर बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहे हैं।

भारत और इजरायल की समझदारी भी किसी से छिपी हुई नहीं है। यदि ग्रेटर इजरायल और ग्रेटर इंडिया का स्वप्न साकार हुआ तो दोनों मजबूत पड़ोसी बन जाएंगे। उधर ग्रेटर रूस बनने से वह भी हमारा पड़ोसी बन जाएगा। इससे अमेरिका व चीन के लिए यूरोप और एशिया में कोई जगह नहीं बचेगी, जबकि रूस का एक छत्र राज बढ़ेगा।

यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ दगाबाजी की है, उसी तरह से उनके सहयोगी भी अब उनसे दगाबाजी कर रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंफ ने अपने सहयोगियों की आलोचना की है और दुनिया भर से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की बात की है।

स्वाभाविक है कि इससे रूस और चीन को फायदा होगा, जो यूरोप और एशिया में अमेरिकी सुरक्षा के खिलाफ ही सालों से काम करते आए हैं। यही वजह है ट्रंप की परिवर्तित नीतियों से सबसे ज्यादा डर अमेरिका के सहयोगियों में है।

बता दें कि कारोबारी से राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे प्यारा शब्द डील है। खासकर यदि बात चीन, रूस और भारत की हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति और ज्यादा खुलकर सामने आ जाते हैं। दरअसल चीन, रूस और भारत से डील कर ट्रंप अपने अमेरिका में एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। वह यह कि वो उन नेताओं से डील कर सकते हैं, जिन्हें निगोसिएशन के टेबल पर लाना सबसे मुश्किल काम है।

बता दें कि एक अमेरिकी अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के साथ व्यापार को सामान्य करना चाहते हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि वे यूक्रेन के साथ युद्ध को सुलझाने के लिए मॉस्को पर दबाव कम करने का ऑफर दे रहे हैं। इसके साथ ही, वे चीन के नेता से फोन करने का आग्रह करके अपने वैश्विक व्यापार पर पड़ रहे छाया युद्ध के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं, एक अन्य अमेरिकी मैग्जीन को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने दो टूक कहा है कि 'हम सभी डील करना चाहते हैं। क्योंकि मैं यानी अमेरिका एक विशाल स्टोर है। यह एक सुंदर स्टोर है जहां हर कोई यानी प्रत्येक देश खरीदारी करना चाहता है।'

ऐसे में अमेरिकी अखबार का कहना है कि ट्रंप के दिमाग में रूस, चीन और भारत को लेकर कुछ और भी बड़ा हो सकता है। तब यह एक बहुत बड़ी डील होगी। लेकिन कुछ विदेश नीति विश्लेषकों का कहना है कि उनके कार्यों और बयानों से पता चलता है कि वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ तीन ही बड़ी ताकतें हैं- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। इन्हें मिलकर भारत का शोषण करना चाहिए। अमेरिका उन्हें रास्ता दिखाएगा और उनके घाटे को लाभ में बदल देगा।

ईरान-इजरायल युद्ध से दुनिया के सामने नई चुनौती

ईरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ इजरायल पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। उधर, इजरायल इस बात पर अड़ा है कि जब तक वह ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता और मिसाइलों के जखीरे को खत्म नहीं कर देता है तब तक हमले जारी रहेंगे।

ईरान-इजरायल युद्ध से पूरे पश्चिमी एशिया में अनिश्चितता और अशांति का माहौल

इजरायल ने ईरान के 'परमाणु कार्यक्रम ठिकानों' पर अचानक हमला करके न सिर्फ दुनिया को चौंका दिया है बल्कि पश्चिमी एशिया के पूरे क्षेत्र को अनिश्चितता, भय, अशांति एवं संकट के भंवर में डाल दिया है। ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल को करारा जवाब दे रहा है। जहां इस्त्राइल इन हमलों को अपने अस्तित्व को बचाने की कार्रवाई बता रहा है, वहीं ईरान जवाबी कार्रवाई कर शीघ्र बदला लेने की बात कर रहा है। लेकिन इन दो राष्ट्रों के संघर्ष एवं युद्ध में समूची दुनिया पीस रही है।

एक और युद्ध से दुनिया में विकास का रथ थमेगा, महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, व्यापक जनहानि होगी। युद्ध कभी भी किसी के हित में नहीं होता, आखिर समझौते के लिये टेबल पर बैठना ही होता है, तो पहले ही टेबल पर क्यों न बैठा जाये? विनाश एवं सर्वनाथ करने के

ललित कुमार

बाद युद्ध विराम करना कैसे बुद्धिमत्ता है?

इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है, जो बताता है कि यह अपने आप में महज एक कार्रवाई नहीं बल्कि नया सिलसिला हो सकता है। हमलों का व्यापक एवं विनाशकारी रूप भी इसकी गंभीरता को स्पष्ट कर देता है। कम से कम छह राउंड में किए गए हवाई हमलों के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों को निशाना बनाया गया। यही नहीं, ईरान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के चीफ हुसैन सलामी के भी मारे जाने की खबर है। ईरान ने तो जवाबी कार्रवाई का इरादा जता ही दिया है, खुद इजरायल सरकार ने भी अपने नागरिकों से अगले कुछ दिन घरों के अंदर रहने और खाने-पीने का सामान इकट्ठा कर लेने को कहा है। इजरायली कार्रवाई के वैश्विक दुष्प्रभावों का संकेत इसी एक तथ्य से मिल जाता है कि पहले हमले के कुछ घंटों के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 13 प्रतिशत बढ़ गईं।

दुनिया के शैयर बाजार धराशायी हो गये हैं। इसमें दो राय नहीं कि इजरायल लंबे समय से कहता रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से हर हाल में रोका जाए और जरूरी हो तो उसके लिए बल प्रयोग से भी हिचका न जाए। उसका कहना है कि ईरान इस स्थिति में आ गया था कि कुछ दिनों के अंदर 15 परमाणु बम बना सकता था। एक भयानक संशय का वातावरण बना

हुआ है। पहले रूस-यूक्रेन, इजरायल-हमास, कुछ समय भारत-पाक और अब इजरायल-ईरान के बीच युद्ध की स्थितियां बनना विश्व युद्ध की संकटपूर्ण स्थितियों को बल दे रही है। संशय से भरा हुआ आदमी प्रेम एवं मानवीयता से खाली होता है। पारस्परिक स्नेह, सद्भाव, सौहार्द और विश्वास के अभाव में उसका संदेहशील मन सदैव युद्ध, हिंसा, सुरक्षा के साधन जुटाने में संलग्न रहता है। उसका मन कभी निर्भय नहीं होता, वृत्तियां शान्त नहीं होतीं, संग्रह उसके सुख, संतोष और शांति को सुरसा बन लील जाता है।

जिसने परमाणु-शस्त्रों के निर्माण और फैलाव से विश्व को तनाव और संत्रास का वातावरण दिया, अनिश्चय और असमंजस की विकट स्थिति दी, उसने विश्व शांति के धरातल छिन लिया है। इन विनाशकारी स्थितियों में मानवीय सहृदयता, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की भावना को कैसे अक्षुण्ण रखा जा सकता है? अभय का वातावरण, शुभ की कामना और मंगल का फैलाव कर तीसरी दुनिया को विकास के समुचित अवसर और साधन देने की संभावनाएं कैसे बलशाली बन सकती है? मनुष्य के भयभीत मन को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति देना वर्तमान की बड़ी जरूरत है। क्योंकि वर्तमान युद्ध की जटिल से जटिलतर होती परिस्थितियों को देखें तो यह पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया और समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक समय है। यदि अन्य देश भी इस संघर्ष में खेमेबाजी का शिकार होकर जुड़ते गए तो यह खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अच्छी बात यही है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत के लिए बेहतर यही होगा कि शांति एवं कूटनीतिक विकल्पों की वकालत करता रहे, लेकिन उसे खुद भी किसी भी प्रकार की स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा।

दुनिया में पहले से ही काफी उथल पुथल मची हुई है। अरब देश संघर्ष लंबा खिंचने पर क्या रूख अख्तियार करते हैं। मुस्लिम देशों की जनता में यह सोच पहले से है कि यहूदी सरकार मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। ऐसे में उनके लिए भी अपनी जनता की भावनाओं को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। वहीं इजरायल के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर उसने संघर्ष शुरू किया है तो वह ईरान के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करे। ऐसे में इजरायल का सैन्य अभियान लंबा चल सकता है। वह लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध को जारी रख सकता है। इसके लिए ईरान की सत्ता में बदलाव या राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करना होगा। यहां अमेरिका का समर्थन अहम होगा। बेहतर होगा दुनिया को भारी नुकसान से बचाने के लिये पूतिन एवं ट्रंप युद्ध की आग बुझाने की कोशिश करें। उनका आपस का दोस्ताना संवाद फिलहाल दुनिया के लिये अकेली उम्मीद की किरण है, हालांकि यूरोपीय संघ को और विशेषतः चीन कुछ हद तक यह अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन युद्ध के अंधेरों एवं शांति के उजालों के लिये यही एक रास्ता है।

ईरान पर इजरायल के हमले ने पहले से युद्धरत एवं अस्थिर दुनिया को अधिक वैश्विक संघर्ष की ओर ढकेल दिया है। ईरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ इजरायल पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। उधर, इजरायल इस बात पर अड़ा है कि जब तक वह ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता और मिसाइलों के जखीरे को खत्म नहीं कर देता है तब तक हमले जारी रहेंगे। अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। आगे चलकर इसमें अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियां शामिल हो सकती हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले ही दो खेमों में बंटी दिख रही है। ईरान ऐसी जगह पर हैं, जहां से वह बहुत सीमित संसाधनों के साथ समुद्र से होने वाले वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकता है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा सकती है, विश्व व्यापार ठप्प हो सकता है और विश्व में तेल आपूर्ति का संकट पैदा हो सकता है।

इजरायल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। खासकर उसे लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यह खतरा इजरायल के साथ अन्य देशों के लिये भी होगा। इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। जो आपरेशन शुरू किया है, उसे लक्ष्य हासिल होने तक जारी रखेंगे। ईरान का परमाणु शक्ति बनना एक बड़ा खतरा है, इस बड़े खतरे को समाप्त करना ही ऑपरेशन राइजिंग लायन का लक्ष्य है। इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आना भी इजरायल के बेहतर मौका लेकर आया और यहां अमेरिका का समर्थन अहम हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिये कहा है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को बार-बार खारिज किया है। बहरहाल, इस घटनाक्रम से मध्यपूर्व में इजरायल-ईरान के बीच सीधे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि इजरायल और हमास, हिजबुल्ला व हूती विद्रोहियों के बीच पहले से जारी संघर्ष से संवेदनशील बने इलाके में पूर्ण युद्ध की आशंका बढ़ गई है।

इजरायल और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसके जटिल परिणाम सामने आते हैं और सभी जीवन-निर्वाह की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जिससे भारतीय रूपया कमजोर होने, मुद्रास्फीति बढ़ने और देश की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ने का खतरा भी है। भारत अपनी जरूरतों का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, ऐसी घटनाओं का महंगाई से लेकर व्यापार संतुलन, रोजगार से लेकर जीवन-निर्वाह तक के महत्वपूर्ण संकेतकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष भारत के हितों को चोट पहुंचाने वाला है। आर्थिक हित के साथ दोनों देशों के साथ भारत के सामरिक तथा रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। भारत को संतुलित रवैया अपनाना होगा, क्योंकि ईरान हमारा पुराना मित्र है, जो कश्मीर मुद्दे को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन तक भारत का साथ देता रहा है। इजरायल हमारा महत्वपूर्ण सामरिक एवं नवाचार साझेदार है। किसी के भी पक्ष में झुकाव दुविधा को ओर बढ़ायेगा।

ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले से हो सकता है विकिरण

मनोज शर्मा

ईरान के एक साथ तीन परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले से परमाणु रिसाव होता है तो बहुत बड़े भू-गर्भ और भूमि क्षेत्र पर विकिरण का खतरा पैदा हो सकता है। यह हमला ईरान के परमाणु संवर्धन प्रतिश्ठान फोदों, नतांज और इस्फहान पर अत्याधुनिक बी-2 घातक बम गिराए गए हैं। इन बमों को सटीक निषाने पर दागने के लिए अमेरिकी पनडुब्बियों ने पहले दो मिसाइलों से बम गिराए, जिससे बंकर बस्टर बमों के लिए मैदान साफ हो जाए। इसके बाद बमवर्षकों ने आसमान से एक के बाद एक 14 जीबीयू-57 बी बंकर बस्टर दाग दिया। इस पूरे अभियान को नतीजे तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ने 15 युद्धक विमानों का इस्तेमाल किया। उपग्रह द्वारा निर्देशित 2400 किलो परमाणु विस्फोटक साथ ले जाने वाला यह बम जमीन में घूमता हुआ 60 मीटर गहराई तक जाने के बाद विस्फोट करके अपने लगक्ष्य को साधने में सफल हो जाता है। अमेरिका ने तीनों ठिकानों पर 14000 किलो विस्फोटक वाले बम गराए हैं। बावजूद ईरान ने हमले को स्वीकारते हुए कहा है कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन परमाणु हथियारों में रिसाव होता है तो बड़ी मात्रा में विकिरण फैल सकता है।

अमेरिका ने जिन तीन परमाणु स्थलों पर हमला किया है, वह सभी ईरान के प्रमुख यूरेनियम संवर्धन ठिकाने हैं। यहां संयंत्रों में प्राकृतिक यूरेनियम को अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम में बदला जाता है। इसी यूरेनियम को प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। परमाणु बिजली बनाने के लिए 3-5 प्रतिषत का यूरेनियम संवर्धन पर्यापत होता है, लेकिन हथियार बनाने के लिए यूरेनियम-235 संवर्धन की जरूरत होती है। यह हमले जिस तादाद में किए गए हैं, उससे बड़े पैमाने पर परमाणु विकिरण रिसाव की आषंका जताई जा रही है। परमाणु बम युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक विस्फोटाकों और रसायनों से भिन्न होते हैं। ये बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, यह ऊर्जा अनेक कड़ियों में रसायनिक प्रक्रियाएं आरंभ कर देती हैं। जो व्यापक और दीर्घकालिक क्षति पहुंचा सकती है। परमाणु

हथियार कुछ ही पलों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जो आसपास के वायुमंडल को लाखों डिग्री सेल्सियस तक गरम कर देती हैं। इस विस्फोट से अनेक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण फैल जाते है, जो अत्यंत घातक होते हैं। हालांकि ईरान के इन ठिकानों में रखे परमाणु हथियारों में विस्फोट की कोई आषंका नहीं है। क्योंकि विस्फोट के लिए परमाणु उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। जो हमलों से संभव नहीं है, लेकिन इनमें रिसाव हो जाता है तो ऐसे में रासायनिक और रेडियोलाजिकल रिसाव दोनों ही संकट में डालने वाले होते है। रेडियोलाजिकल रिसाव 1996 में रूस के चेर्नोबिल और 2011 में तूफान आने से जापान के फुकुशिमा में हुआ था। अतएव हमलों के कारण परमाणु विकिरण रिसाव की आशंका बनी हुई है। अमेरिका का यह हमला नटखट बालक की जिद की तर्ज पर उस हद से बाहर चला गया है, जो दुनिया के अंतरराष्ट्रीय कानून और अपने ही देश के कानूनों की परवाह नहीं करता है। इसीलिए अमेरिका के भीतर इस परमाणु हमले को लेकर अमेरिकी जनमत विभाजित दिखाई दे रहा है। दरअसल किसी देश पर हमला करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संसद में हमले का प्रस्ताव लाकर अनुमोदन की जरूरत थी। परंतु उन्होंने इस प्रक्रिया पर अमल नहीं किया। जबकि अमेरिका की ही बात करें तो अप्रैल 2003 में ईराक पर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल के लिए हमला किया था तब तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने संसद से मंजूरी ली थी। इसलिए ट्रंप के समर्थकों के साथ विपक्ष भी नाराज है।

अंतरराष्ट्रीय कानून परमाणु बम के उपयोग को मानवता के विरुद्ध अमानुशिक कृत्य मानते हैं। इनके उपयोग के बाद संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद (यूएनएससी) के कठोर आर्थिक व राजनीतिक प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वे सब अमेरिका या अन्य पष्चिमी देषों के दबाव में रहती हैं। यही देष इन संस्थानों को चलाने के लिए धन मुहैया कराते हैं और इन्हीं देषों के लोग इन संस्थानों के सदस्य होते हैं, इसलिए यहां पक्षपात साफ दिखाई देता है। अतएव ईरान में परमाणु विकिरण फैल भी जाए, तब भी अमेरिका के विरुद्ध कोई प्रतिबंध लगाना असंभव है। ब्रिटिष प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने तो कहा है कि यह संघर्श बड़ा रूप ले सकता है। अतएव संकट का कूटनीतिक हल निकालना जरूरी है। इसलिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना जरूरी है। उसे समझौते के लिए बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान के विदेष मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिका ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है, कूटनीति का समय समाप्त हो गया है, अतएव ईरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। साफ है, तनाव और युद्ध फिलहाल बने रहेंगे।

ईरान ने अमेरिकी सहयोग से 1957 में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था। 1970 में परमाणु बिजली घर बना लिया था। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान को सहयोग करना बंद कर दिया। बावजूद पश्चिमी देश ईरान पर परमाणु बम बना लेने का आरोप लगाते रहे। परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने के बाद भी ईरान पर शंकाएं की जाती रहीं। इजरायल ने जासूसी करके कुछ ऐसे सबूत जुटाए, जिनसे यूरेनियम संवर्धन की आशंका मजबूत हुई। 2000 में वैष्विक परमाणु निरीक्षकों को नतांज में सवंर्धित यूरेनियम मिला। हालांकि ईरान ने पहले संवर्धन रोक दिया था, लेकिन इजरायल की बढ़ती सामरिक क्षमता के चलते उसने गुपचुप परमाणु कार्यक्रम षुरू कर दिया था। इस कारण ईरान पर पष्चिमी देषों ने यह कहते हुए अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे कि ईरान परमाणु बम बनाने के निकट पहुंच गया है। बाद में कई साल चली वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रतिबंध कहटा लिए थे। इस समझौतें में ईरान को असैन्य यूरेनियम संवर्धन को 3.67 प्रतिशत तक रखना मान्य कर लिया था। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने समझौते से हाथ खींच लिए और ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। 2023 में आईएईए ने कहा कि ईरान में 83.7 प्रतिशत शुद्धता के यूरेनियम कर्ण मिले हैं और उसके पास 128.3 किलो संवर्धित यूरेनियम है। मई 2025 में आईएईए ने दावा किया कि ईरान के पास 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम की मात्रा 408 किलो है। इससे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते है। इसे ही नश्ट करने को लेकर इजरायल ने ईरान पर हमला किया और अब अमेरिका इस लड़ाई में कूंद पड़ा है। अब यह लड़ाई बबार्दी के किस मुकाम पर पहुंचती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है।

दुनिया को अस्थिरता की ओर अग्रसर करते युद्ध !

हरेन्द्र शर्मा

आज पूरी दुनिया दुनिया बारूद के ढ़ेर पर खड़ी हुई है। कहना गलत नहीं होगा कि आज विश्व में हर तरफ युद्ध, अशांति, तनाव और अस्थिरता का साया नजर आ रहा है। पहले रूस-यूक्रेन युद्ध, बाद में इजरायल और हमास के बीच युद्ध और अब इजराइल-ईरान के बीच भी युद्ध प्रारम्भ हो गया है। पाठक जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच भी युद्ध छिड़ गया था, परंतु अमेरिका की भूमिका के चलते इस युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करने में सफलता मिल गई थी।

हालांकि, यह बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भारत पाकिस्तान मध्यस्थता पर दो टूक बातें कहीं हैं कि भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष(अमेरिका) की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और भविष्य में भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल, भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर के लिए बार-बार मध्यस्थता का दावा कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह साफतौर पर स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के अनुरोध पर रोकी थी न कि अमेरिकी मध्यस्थता या व्यापार समझौते की पेशकश के कारण। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि ईरान इजरायल युद्ध पर दुनिया दो फाड़ होती नजर आ रही है। अमेरिका इजरायल का तो वहीं दूसरी ओर रूस ईरान का समर्थन कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो वहीं रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को यह खुली धमकी दी है कि यदि अमेरिका जंग में कूदता है तो अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पावरफुल चीन ने भी ईरान का समर्थन किया है और इजरायल से सीजफायर (युद्ध विराम) करने को कहा है। पाठकों को बताता चलूं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दो टूक लहजे में यह कहा है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का सही तरीका युद्ध कभी नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले चीन ने पांच दिनों की जंग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि बीजिंग इस गहराते युद्ध से चिंतित है। हालांकि, ईरान ने जोर देकर यह बात कही है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि ईरान-इजरायल के बीच युद्ध से दोनों देशों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बतातीं हैं कि इस युद्ध में दोनों ही देश पानी की तरह पैसा बहा रहें हैं, ऐसे में इनकी जीडीपी में गिरावट आ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस युद्ध में इजरायल को हर दिन करीब 725 मिलियन डॉलर (करीब 6300 करोड़ रुपये) का सिर्फ सैन्य खर्च हो रहा है। रिपोर्ट्स बतातीं हैं कि इजरायल ने शुरूआती दो दिनों में ही करीब 1.45 अरब डॉलर (12000 करोड़ रुपये से ज्यादा) खर्च कर दिए।इसमें हमले और बचाव दोनों तरह के खर्चे शामिल हैं। इसमें

से 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम, तो बमबारी और जेट ईंधन जैसे हमलों पर ही खर्च हुई है। बाकी पैसा मिसाइल इंटरसेप्टर और सैनिकों को जुटाने जैसे रक्षा कार्यों पर खर्च हुआ है। इजरायल जहां गाजा में हमास के साथ लड़ाई जारी रखे हुए है वहीं एक अन्य मोर्चे पर वह ईरान से भी लोहा ले रहा है।इस प्रकार से इजरायल की अर्थव्यवस्था पर युद्ध से दोहरा असर पड़ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध के चलते देश के घरेलू उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम 5% तक बढ़ चुके हैं।एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ब्रेंट क्रूड 74.60 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। वहीं, एस एंड पी 500 और एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट आई है। जल मार्गों पर खतरे से ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि दो देशों के बीच युद्ध में किसी एक देश का फायदा नहीं होकर बल्कि दोनों ही देशों का नुकसान ही होता है। वैसे भी कोई भी युद्ध किसी भी समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं होता है। युद्ध विनाश और अशांति को ही जन्म देता है और युद्ध के कारण कोई भी देश बरसों पीछे चला जाता है,उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और युद्ध के बाद किसी भी देश का जल्दी से उबरना मुश्किल हो जाता है। यह एक विडंबना ही है कि आज हर कोई देश छोटी-छोटी बातों को लेकर आवेश में एक-दूसरे से टकरा बैठते हैं और दो देशों के पक्ष एवं विपक्ष में कुछ देश खड़े हो जाते हैं, जिससे कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि विश्व युद्ध छिड़ जाते हैं। वर्ष 1914 से वर्ष 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध एवं वर्ष 1939 से वर्ष 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इजराइल ईरान के बीच हाल ही में प्रारम्भ हुए युद्ध में अमेरिका, रूस और चीन यदि कूद पड़ते हैं, तो यह बहुत सम्भव है यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का स्वरूप ले ले। वास्तव में, सच तो यह है कि इजराइल और ईरान दोनों ही देशों के पास शक्तिशाली सहयोगी हैं। ऊपर जानकारी दे चुका हूं कि इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। इतना ही नहीं,ब्रिटेन और जर्मनी के साथ भी इसकी रणनीतिक साझेदारी है। ईरान के भी अपने कुछ सहयोगी हैं। जो भी हो मध्य-पूर्व में हालात कुल मिलाकर ठीक नहीं हैं। आज विश्व के बड़े देश अपने यहां परमाणु हथियारों की बढ़त करने में लगे हैं।सच तो यह है कि वैश्विक स्तर पर आज परिस्थितियां बहुत सहज रूप से नहीं चल रही हैं। यह बहुत ही दुखद है कि आज कुछ देश अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा देने में लगे हैं तो कुछ बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। पाठकों को बताता चलूं कि इजराइल भी भारत की तरह आतंकवाद से पीड़ित देश है तथा इजराइल की सीमाएं चार मुस्लिम राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं, यथा, उत्तर में लेबनान, दक्षिण पश्चिम में ईजिप्ट (एवं गाजा), पूर्व में जॉर्डन (एवं वेस्ट बैंक) एवं उत्तर पूर्व में सीरिया। वास्तव में, इजराइल अत्यधिक आक्रात्मकता के साथ आतंकवादियों (हमास एवं हिजबुल्ला आदि संगठनों) से युद्ध करता रहता है। इस्लाम के अनुयायी यहूदियों के कट्टर दुश्मन हैं, इसके चलते भी इजराइल के नागरिकों को आतंकवाद को लम्बे समय से झेलना पड़ रहा है।दूसरी तरफ ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। अंत में यही कहूंगा कि आज दुनिया के सामने आर्थिक चुनौतियां लगातार बड़ी होती जा रही हैं। वहीं, क्लाइमेट चेंज(जलवायु परिवर्तन) भी हमारी चिंताएं बढ़ा रहा है। वास्तव में युद्ध दुनिया को लगातार अस्थिरता की ओर ले जा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि ये तनाव और खतरे, यदि हल नहीं किए जाते हैं, तो आने वाले समय में ये एक बड़ी वैश्विक आपदा का कारण बन सकते हैं। वास्तव में, विश्व को आज असमानता और अनिश्चितता से निपटने की नितांत आवश्यकता है।

ऐसे तो ट्रंप को नहीं मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार

डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए हैं। पूरे चार वर्ष हैं उनके पास। वे अपने दुश्मनों से दोस्तों को लड़ाकर रास्ते पर रहें या हट जाएं, उनकी राष्ट्रपति वाली कुर्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस और ईरान अमेरिका के परंपरागत शत्रु हैं।

अमेरिका के दूसरी बार बने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने को दुनिया का शांति का अग्रदूत साबित करने में लगे हैं। वे कहते रहे हैं कि भारत-पाकिस्तान युद्ध उनके कहने पर रूका। रूस-यूक्रेन युद्ध रूकवाने के लिए वे प्रयासरत है। वे चाहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिले, उधर वह ईरान पर हमला करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया है। इससे इजरायल-ईरान युद्ध रूक जाएगा। उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है और लग रहा है कि इस हालात में तो उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। ऐसे में तो उन्हें इस तरह की सफलता के साथ ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।

डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए हैं। पूरे चार वर्ष हैं उनके पास। वे अपने दुश्मनों से दोस्तों को लड़ाकर रास्ते पर रहें या हट जाएं, उनकी राष्ट्रपति वाली कुर्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस और ईरान अमेरिका के परंपरागत शत्रु हैं। उन्होंने नाटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को ताकतवर रूस से भिड़ा दिया, इससे यूक्रेन तो बर्बाद हो ही गया। रूस की भी बड़ी शक्ति इस लड़ाई में व्यय हो रही है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के तथाकथित तीन परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम है। परमाणु बम बनाने वाले तीनों केंद्रों पर उन्होंने हमला किया है, जबकि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा

सलाहकार तुलसी गैबार्ड कह रही हैं कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। पुतिन बता रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। अमेरिका ने ही इजरायल से कहा कि यहूदियों का खत्मा करने के लिए ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, यह कह कर उसने इजरायल को ईरान से भिड़ा दिया ।

अमेरिका के इस हमले के बाद रूस और चीन का क्या रवैया रहेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ, हो सकता है कि यह खुल कर ईरान के साथ न आएं किंतु युद्ध सामग्री और तेजी से ईरान को उपलब्ध कराएंगे। ईरान की जरूरत के घातक हथियार उसे बेचेंगे। किंतु अगर ये खुलकर सामने आ गए तो है कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। लगता है कि ट्रंप ने ईरान में हमला करके पूरे विश्व की शांति को खतरे में डाल दिया। इससे सारे मुस्लिम देश एक मोर्चे पर आ जाएंगे। उम्मीद है कि इस हमले के बाद यमन के मुस्लिम आंतकी संगठन अमेरिका के विरूद्ध एकजुट हो जाएंगे।

अमेरिका ने रूस को तोड़ने के लिए ओसामा बिन लादेन जैसे आंतकी को इस्तेमाल किया। उन्हें प्रश्य दिया। अमेरिका के इराक पर हमले से लादेन नाराज हो गया। उसने अमेरिका के ट्रेड सैंटर पर हमला कर इसका बदला लिया। अब फिर मुस्लिम आंतकी संगठन एक हो अमेरिका के विरूद्ध खड़े हो जाएंगे। इस क्षेत्र में ईरान के सहयोगी मिलीशिया, जिनमें यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्ला और इराक के सशस्त्र समूह, लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं। पिछले दो साल में उनमें से कई गंभीर रूप से कमजोर हो गए हैं, फिर भी वे ईरानी सहयोगी लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। इस्लामिक आंतकी संगठन हूती और लेबनान में हिजबुल्ला ने दक्षिण में एक महत्वपूर्ण तेल शिपिंग चैनल, रेड सी और बाब एल मंडेब जलडमरूमध्य पहले भी इजरायल समर्थक कटेनर ले जाने वाले जहाज पर पहले भी हमला कर चुके हैं। अब ये जलडमरूमध्य को बंद करके या उसमें यातायात को बाधित करके वैश्विक तेल की कीमतों में तेजी जरूर पैदा कर सकते हैं, जो अब अमेरिकी हमले के बाद और ऊँची जाएगी। यहां से गुजरने वाले अमरिकी समर्थक देशों के शिपिंग कंटेनर पर ही नहीं और भी अमेरिकी समर्थक देशों पर हमले और बढ़ेंगे।

जहां तक भारत का सवाल है, इजरायल और ईरान दोनों भारत के घनिष्ट मित्र हैं। भारत का प्रयास होगा कि युद्ध रूके। भारत रूस-यूक्रेन युद्ध के समय से ही कहता आ रहा है कि यह समय युद्ध का नहीं है।

ट्रंप भी अब तक भारत के सबसे बड़े मित्रों में से एक थे। लेकिन ट्रंप ने अपने स्वार्थों की खातिर भारत के दुश्मन पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान से हाथ मिलाने का उसका मंतव्य भी स्पष्ट हो गया। सूचनाएं आ रही है कि ईरान पर हमले के लिए उसने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तमाल किया। ट्रंप ने हजारों करोड़ डॉलरों का लालच देकर पाकिस्तान को इस्लामिक जगत में नंगा कर दिया और पाकिस्तान को पता भी न चला? यह तय है कि इसमें बाद अमेरिका पाकिस्तान को और ज्यादा मदद देगा, विमान और शस्त्रों की आपूर्ति करेगा।

भारत जो अब तक अमेरिका से आधुनिकतम लड़ाकू विमान और शस्त्र प्रणाली खरीदने की बात कर रहा था। उसे इस घटनाक्रम से चौकस होना होगा। यही वजह है कि भारत अब रूस से 5.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन खरीदने की तैयारी में है। यही विमान अमेरिका हमें बेचना चाहता था। भारत पहले ही अपने शस्त्र और युद्धक विमान विकसित कर रहा था, उसे अब और चौकस होकर देश की सुरक्षा की रणनीति बनानी होगी।

ईरान ने अभी तक इजरायली हमलों का जवाब मिसाइल-प्रहारों से दिया है, लेकिन उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों या ठिकानों पर हमला करने से परहेज किया है। उसने सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी अरब देशों पर भी हमला नहीं किया है। शुक्रवार को ईरानी विदेशमंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, तो देश को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे में यदि ईरान अमेरिका और मित्र देशों पर हमला करता है तो युद्ध भड़क सकता है।

एक बात और पूरी दुनिया के देशों को सोचना होगा कि क्या किसी एक देश को ये ठेकेदारी दी जा सकती है कि वह तै करे कि कौन देश कौन सा हथियार रखेगा, कौन सा नहीं। प्रत्येक देश को अधिकार है कि यह अपनी देश की जरूरत के हिसाब से हथियार खरीदे और विकसित करें। अमेरिका और मित्र देश नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु बम बनाए। वह उसे आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए धमका रहे थे। उसके बाद भी भारत ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। इसके बाद अमेरिका और मित्र देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। ऐसा ही भारत के रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम खरीदते हुआ था। अमेरिका ने भारत को बार-बार आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। उधर भारत ने अमेरिका से लडाकू विमान के इंजन लेने का सौदा किया, किंतु निर्धारित अवधि के काफी बाद भी भारत को इंजन नहीं मिले। इससे साफ हो जाता है कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी तो अमेरिका के दुश्मन देश की हो। यह भी कि उसे अपनी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। चीन भारत का दुश्मन देश है। फिर भी वह कभी भारत का सगा नहीं हो सकता। ऐसे में बस रूस ही बचा है। वह भारत का अजमाया और विश्वसनीय दोस्त है। वर्तमान हालात में उस पर भी पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह यूक्रेन युद्ध में चीन पर निर्भर होता जा रहा है ऐसे में हमें होगी। स्वनिर्मित प्रणाली के बूते पर अपनी युद्ध नीति स्वयं बनानी।

कितना फायदेमंद रहेगा 'फास्टैग' का नया नियम?

टोल टैक्स पर आए दिन घटित होती नाना प्रकार की सामान्य-असामान्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आखिरकार केंद्र सरकार ने एक दफे फिर पुरानी टोल्स नीतियों में बदलाव करते हुए नए फास्टैग नियम लागू करने का ऐलान किया है। बदले नियमों को केंद्र सरकार नसुपरफास्ट फास्टैग बताया है। हालांकि, ये नवीनतम योजना दो महीने बाद यानी आगामी 15 अगस्त से देशभर में अमल आएगी। इसके संबंध में मोटी-मोटी सूचनाएं विभागीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते गुरुवार को सोशल मीडिया मंच ह्यएक्सह्ल के जरिए देशवासियों से साक्षा की। नई नियमों को लेकर लोगों के जेहन में सिर्फ दो सवाल प्रमुखता से उठ रहे हैं। अव्वल, क्या अब टोल टैक्स पर लगने वाली लंबी-लंबी कतारें कम होंगी। वहीं दूसरा, क्या इससे वाहन चालकों को थोड़ी बहुत रियारत मिल पाएगी? गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐलान किया

जितेन्द्र कुमार

था कि 60 किमी अंतराल में आने वाले टोल से वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन अफसोस वह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। कम दूरी वाले किसी टोल को बंद नहीं किया गया, आज भी टोल्स पर वसूली बदस्तूर जारी है। ज्यादातर पुराने टोल की दूरी 60 किमी से काफी कम हैं। 30-40 किमी की दूरी में ही बने हैं। विगत सालों पहले सरकार ने टोल से नगद वसूली के नियमों को बदलकर जब से फास्टैग योजना को लागू किया था, तब से उसकी आमदनी में चार चांद लग गए। दरअसल, फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जिसे एनएचएआई लीड करती है। फास्टैग से टोल वसूली का पैसा धीरे सरकार के खजाने में जाता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक से उपयोग होती है, जिससे ग्राहक टोल भुगतान सीधे प्रीपेड या बचत खाते से आसानी से करते हैं। वित्तीय वर्ष-2024 में भारत भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह राजस्व का मूल्य 648 बिलियन भारतीय रुपए से अधिक रहा। यही कारण है कि सरकार इस सब्जेक्ट को इतनी गंभीरता से लेकर चल रही है। सरकार का मकसद है कि नए नियमों का फायदा ग्राहकों को भी हो और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो? केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 और शुल्क नियम-2008 के तहत टोल प्लाजा के माध्यम से शुल्क वसूलती है। नियमों में बदलाव पहले भी कई मर्तबा किए गए। पर, बीते एकाध दशक से टोल वसूली में बेहताशा इजाफा हुआ। जिसे कम करने का आमजन का भारी दबाव सरकार पर है। आम लोगों को मिलने वाली किफायत की जहां तक बात है, तो नई पॉलिसी फिलहाल निजी वाहनों पर लागू

होगी। तीन हजार रुपए का वैध वार्षिक पास बनवाने के बाद ग्राहक साल भर की अवधि में 200 टोल टैक्स क्रॉस कर सकेंगे। ये पास मौजूदा फास्टैग में ही संचालित होगा, नया बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, इसमें पेंच एक फंसाया गया है। योजना सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और विभिन्न राष्ट्रय राजमार्गों में प्रयोग होगी। राज्य स्तरीय मार्गों-सड़कों, निकाय और नगर निगम की अधिकृत सड़कों को इससे नहीं जोड़ा गया है। योजना से ग्राहकों को जो फायदा होगा, वह ये है कि अभी तक अमूमन प्रत्येक एनएचएआई टोल टैक्स पर भुगतान करने की कीमत 50 रु से लेकर 200 रुपए के बीच होती है। लेकिन 3 हजारी वैध पास के बाद मात्र 15 रूपए ही प्रत्येक टोल पर वसूले जाएंगे। ये फायदा निजी वाहन चालकों को सीधे तौर होगा। योजना की एक अच्छी बात ये है। चालक अगर साल में 200 टोल्स को क्रॉस नहीं करता है, तो उसकी वैधता अगले वर्ष भी जारी रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोजाना और नियमित चलने वालों के लिए 'सुपरफास्ट फास्टैग' योजना निश्चित रूप से कारगर साबित होने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय पर बीते कुछ वर्षों से टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को कम करने का भारी प्रेसर पड़ा है। प्रत्येक दिन कहीं न कहीं मारपीट की घटनाएं रिपोर्ट होती रही हैं। इन सभी से छुटकारा पाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना को लागू किया। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विशाल नेटवर्क बिछ चुका है। वर्ष-2014 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो चुकी है। अगले 10 सालों में राजमार्गों की लंबाई डेढ़ गुनी तक बढ़ने की संभावनाएं हैं और उसमें नए टोल भी जुड़ेंगे। इसलिए सरकार के लिए ये क्षेत्र

कमाई का बड़ा जरिया बन गया है। सरकार को नेशनल हाईवे से प्रति वर्ष पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत चलने वाले टोल बूथों पर टैक्स के तौर पर 1.44 लाख करोड़ रुपये की कमाई हो रही है। इस आंकड़े को पिछले वर्ष का खुद नितिन गडकरी ने संसद में प्रस्तुत किया था। देश में सड़कां का जिस युद्वस्तर पर जाल बिछ रहा है, उससे प्रतीत होता है भविष्य में यह क्षेत्र सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनेगा।आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में करीब 1,063 टोल प्लाजा हैं जिनमें 457 टोल प्लाजा का निर्माण वर्ष 2025 में किया गया। टोल नीति केंद्र सरकार की वह इकाई है जो सबसे बड़ी कमाउ है। नई ह्यसुपरफास्ट फास्टैगह्न नीति से भी उसे ढेरों उम्मीदें हैं। टोल पॉलिसी को केंद्र सरकार राजस्व वसूली का सबसे बड़ा जनरेटर मानती ही है, तभी इसमें नित नए नियमों को जोड़ती चली जा रही है। मात्र दिल्ली-मुंबई मार्ग पर एनएच-48 के वडोदरा-भरूच खंड पर स्थित टोल प्लाजा ने पिछले 5 पांच सालों में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाकर दिए हैं।

सहकार ग्रुप लिमिटेड (एसजीएल) भारत में सड़कों के टोल संग्रह में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। टोल से कमाई के आंकड़ों पर अगर नजर डालें, तो 2018-19 में 25,154.76 करोड़ रुपए, 2019-20 में 27,637.64 करोड़ रुपए, 2020-21 में 27,923.80 करोड़ रुपए, 2021-22 में 33,907.72 करोड़ रुपए और 2022-23 में 48,028.22 करोड़ रुपए अर्जित किए। कमाई बढ़े अच्छी बात है, पर सड़कों की सुरक्षाओं को लेकर वाहन चालकों के प्रति जो चिंताएं हैं वह भी कम होनी चाहिए। सरकार को सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा। निर्बाध और सुगम सड़क यात्राओं की इच्छाएं सभी में हैं।

योजना से ग्राहकों को जो फायदा होगा, वह ये है कि अभी तक अमूमन प्रत्येक एनएचएआई टोल टैक्स पर भुगतान करने की कीमत 50 रु से लेकर 200 रुपए के बीच होती है। लेकिन 3 हजारी वैध पास के बाद मात्र 15 रूपए ही प्रत्येक टोल पर वसूले जाएंगे। ये फायदा निजी वाहन चालकों को सीधे तौर होगा। योजना की एक अच्छी बात ये है। चालक अगर साल में 200 टोल्स को क्रॉस नहीं करता है, तो उसकी वैधता अगले वर्ष भी जारी रहेगी।

योग और आयुर्वेदः समग्र स्वास्थ्य संजीवनी

आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री
ज्योर्तिवैद्य

सनातन संस्कृति विश्व कल्याण की संस्कृति है। जिसका उद्देश्य मनुष्य ही नहीं, अपितु प्राणीमात्र का हित है। ऋषियों ने स्वास्थ्य को प्रार्थमिकता की विषयवस्तु स्वीकरते हुए सबके सुख की कामना की है। मानव सभ्यता के आरम्भ से ही यहां सर्वजन हिताय की परंपरा रही है। इसी कारण सनातन के सभी शास्त्र सबके निरामय की बात कहते हैं। हमारी नित्य प्रार्थनाओं में कहा जाता है कि

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्॥

क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया ही कहा गया है। इसीलिए अथर्ववेद से ऋग्वेद तक स्वास्थ्य के सूत्रमंत्र और ऋचाएं मिलती हैं। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। अथर्ववेद ही मूल वेद है और वेदत्रयी (ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद) इसी के भाग हैं।

जैसे नदी के दो किनारे जल के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और प्रवाह को गति प्रदान करते हैं, वैसे ही योग और आयुर्वेद रूपी किनारे जीव के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। जिसके प्रभाव से मनुष्य स्वर्य, परिवार और समाज के स्वस्थ प्रवाह को गति मिलती है और राष्ट्र प्रगति करता है। योग और आयुर्वेद का उद्देश्य मनुष्य को समग्र रूप से स्वस्थ रखना है। समग्र स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करना। जिससे मानव सम्पूर्ण मानव होने की ओर अग्रसर हो। शरीर की गतिविधियां स्वस्थ हों, उचित पोषण हो, समयानुकूल निद्रा हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो, मनोदशा पर नियन्त्रण हो, तनाव प्रबन्धित हो और संचेतना की वृद्धि हो। देखा गया है कि समग्र रूप से स्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्य समाज के प्रति संतुष्ट और लोक कल्याणकारी होता है।

योग

योग शब्द की उत्पत्ति युज् धातु से हुई है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की दृष्टि से इसे तीन प्रकार से प्रयोग किया है।

प्रथम युज् समाद्यौ (दिवादिगण) जिसका अर्थ है समाधि के लिए सिद्धि से जुड़ना। साधनाओं को जीवन में उतारना। द्वितीय युज् योगे (रुधादिगण) जिसका सामान्य अर्थ है मिलना, जुड़ना, जोडना। दुःख रूपी संसार से वियोग और ईश्वर से संयोग।

इसी को भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में स्पष्ट करते हुए कहा था-

तं विद्याद्दुःख संयोग वियोग योग संज्ञितम् ॥

तृतीय युज् संयमने (चुरादिगण) जिसका तात्पर्य है मन का नियमन, संयम अथवा मन पर नियंत्रण प्राप्त करके आत्मा का परमात्मा से मिलन करना।

महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि

अयं तु परमो धर्मो यत्योगेनात्मदर्शनम्॥

अर्थात जिस साधना द्वारा आत्मदर्शन और ब्रह्मसाक्षात्कार होता है, वह योगशास्त्र है। योग साधना से न केवल शारीरिक शक्तियों का विकास होता है, अपितु निरोगता पूर्वक जीवन जीने की कला प्रास होती है। श्वेताश्वरोपनिषद कहता है कि

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः ।
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् ॥

अर्थात् जिस मनुष्य ने योगरूपी अग्नि से अपने शरीर को तपा लिया, वह रोग, वृद्धावस्था और अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है।

वर्तमान में तनाव भरे जीवन में योग के प्रयोग मानसिक रोगों का महत्वपूर्ण निदान है। योग द्वारा चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण करने की कला का विकास होता है, जिससे मन स्वस्थ रहता है। मन के स्वस्थ होने से शरीर की ऊर्जाएं सुव्यवस्थित होती है और ईर्ष्या, घृणा, असंतुष्टि, क्रोध, सशंकित रहने की प्रवृत्ति, कटुता, द्वेषभाव के कारण शरीर दुर्विचारों से दूषित नहीं होता है। रक्त विषयुक्त नहीं होता है, जिस कारण ओजस्विता निरंतर बढ़ती है और तनाव रहित होने से मानसिक एकाग्रता की वृद्धि होती है। क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारक होता है। अतः योग के आध्यात्मिक प्रभावों से तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा होने पर परिवार में शान्ति और समृद्धि की वृद्धि होती है। नकारात्मक चिंतन नष्ट होने लगता है, जो व्यक्ति को समाज में सुसभ्य मानवों की श्रेणी में ला खड़ा करता है और मनुष्य को नैतिकता से जोड़ता हुआ उसके आचरण से असभ्यता के लक्षण नष्ट कर देता है।

योग के षट्कर्म

1. नेतिः नेति नासिका के माध्यम से शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है।
2. धौतिः धौति उदर को शुद्ध करने की क्रिया है।
3. नौलिः नौलि पेट की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और उदरशुद्धि की क्रिया है।
4. वस्तिः वस्ति आंत्रशोधन की महत्वपूर्ण क्रिया है।
5. कपालभातिः कपालभाति फुफ्फुस शुद्धि और प्राणशुद्धि की क्रिया है। यह शरीर को प्रकाशित करती है, रोगों को भस्म करती है और ललाट को कांतिमय करती है।
6. त्राटकः त्राटक एकाग्रता और ध्यान की क्रिया है, जिसमें एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

आयुर्वेद के पंचकर्म

1. वमनः वमन उदर को शुद्ध करने की क्रिया है, जिसमें पेट से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए वमन कराया जाता है।
2. विरेचनः विरेचन आंतों को शुद्ध करने की क्रिया है, जिसमें आंतों से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए विरेचक औषधियों का प्रयोग किया जाता है।
3. वस्तिः वस्ति आंतों की शुद्ध करने की क्रिया है, जिसमें आंतों में औषधीय पदार्थों आंत्रशोधन किया जाता है।
4. नस्यः नासिका मार्ग से शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है, जिसमें नाक में औषधीय पदार्थों को डाला जाता है।
5. रक्तमोक्षणः रक्तमोक्षण रक्त को शुद्ध करने की क्रिया है, जिसमें शरीर से विषाक्त रक्त को निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं।

आयुर्वेद

आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति है आयुषो वेदः अर्थात यह आयु का वेद है। चैतन्य की स्थिति को आयु कहा गया है। अमरकोष में इसे जीवित काल कहा गया है। चरक संहिता में इसे शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा का संयोग कहा गया है। वस्तुतः आयुर्वेद, आयुः वेद, इन दो शब्दों के संयोग से बना है। आयुर्वेद में वेद शब्द विद् ज्ञाने धातु से बना है। जिसका अर्थ है ज्ञान, सत्ता, विचार और प्राप्ति। जिससे अस्तित्व का बोध हो सके, वह ज्ञान वेद कहलाता है। अतः जिस शास्त्र में आयु का जान हो, अस्तित्व हो, आयु की प्राप्ति हो, रोगरहित जीवन की अवस्था प्राप्त हो, वह आयुर्वेद कहाता है। महर्षि चरक के अनुसार

तत्र आयुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रं ज्ञानं शास्त्रं लक्षणं तन्त्रमित्यनर्थान्तरम् ॥

अर्थात शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण, और तन्त्र आयुर्वेद के पर्याय है। जी शास्त्र हितायु, अहितायु, सुखायु और दुःखायु का ज्ञान प्रदान करे, सभी आयु संबन्धी और स्वास्थ्यवर्धक उपचारों और प्रयोगों का ज्ञान देने वाला, शरीर रचना और पथ्य अपथ्य की जानकारी देने वाला, साध्य और असाध्य रोगों की भी चिकित्सा करने वाला शास्त्र है, वह आयुर्वेद है। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि-

आयुकामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

अर्थात् आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान पुरुषार्थ चतुष्ट्य की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। जीवन को आरोग्यमय कर देता है। क्योंकि रोगी व्यक्ति न तो धार्मिक क्रियाएं कर सकता है, न धनार्जन कर सकता है, न आजीविका व्यवस्थित कर सकता है, न सुख सुविधाओं का आनन्द ले सकता है, न मोक्ष की प्रासि कर सकता है और उसका जीवन कठिन परिस्थियों से घिर जाता है। लेकिन आयुर्वेद की शरण में गया मनुष्य न केवल पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सकता है, अपितु आरोग्यमय जीवन की भी प्राप्ति करता है। क्योंकि आयुर्वेद जीवन देने वाला शास्त्र है। इसलिए पुण्य

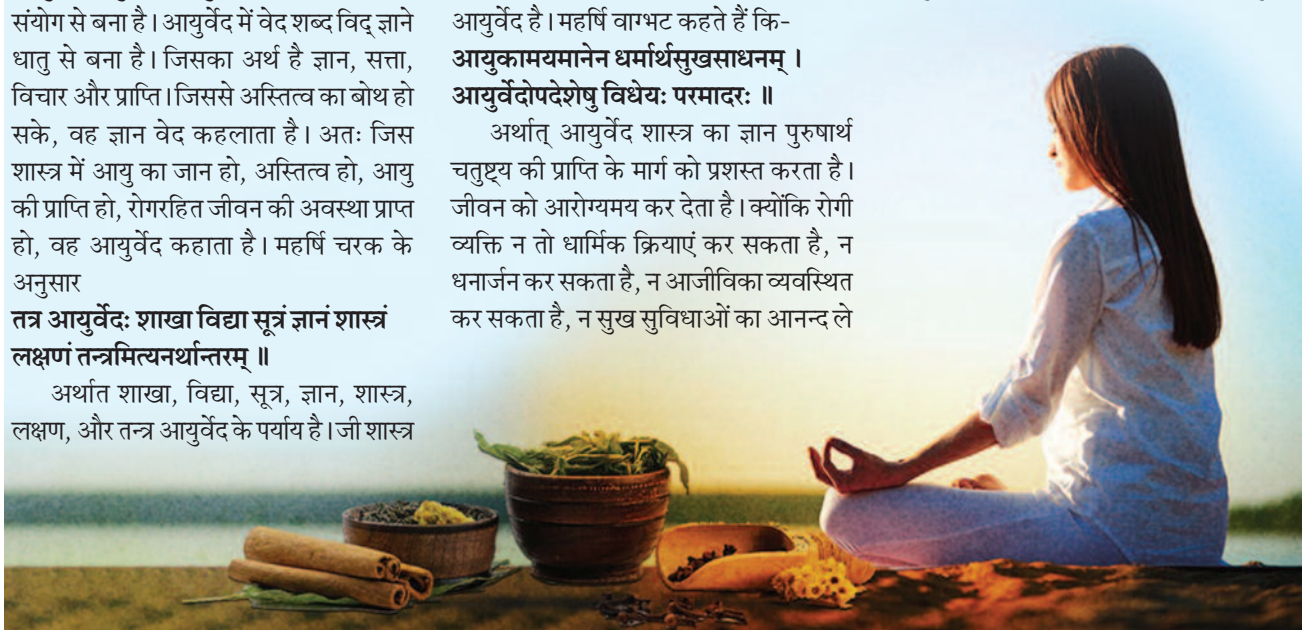

अष्टांग समन्वय

पातंजल योग दर्शन में योग के आठ अंग कहे गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग भी कहा जाता है। इस अष्टांग योग के अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होती है। विवेक जाग्रत होता है। ज्ञान का प्रकाश अन्तस को प्रकाशित करता है। यह जीवन को अनुशासित करता है। यह बहिरंग योग और अन्तरंग योग, दोनों को समाहित करता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग योग हैं और धारणा, ध्यान व समाधि अंतरंग योग कहाते हैं। योग के इन आठ अंगों का अभ्यास मनुष्य को आन्तरिक और बाह्य रूप से न केवल शुद्ध और स्वस्थ करता है, अपितु उसकी मेधा इतनी प्रखर हो जाती है कि वह संसार को चमत्कृत कर सकता है। इनके अभ्यास से मनुष्य जगत को प्रकाशित करने की क्षमता से परिपूर्ण हो जाता है और शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। आष्टांग योग के आठ अंग हैं।

से परिपूर्ण है।

योग और आयुर्वेद में अनेक साम्यताएं हैं। योग से मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और आयुर्वेद योग से युति करे ती यह औषधियों के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कराता है। योग छोटे स्थान पर भी किया जा सकता है और आयुर्वेद की औषधियां सहजता से प्राप्त हो जाती हैं।

योग और आयुर्वेद का संबंध

योग और आयुर्वेद दोनों, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए महान उपयोगी हैं। जीवन को प्रकाशित करने वाली ये दोनों विद्याएं प्रायशः एक सी लगती हैं। जिनके नियमित सेवन से शरीर निरोग रहता है और कर्मशीलता के प्रति जाग्रत होता है। तनाव नष्ट होता है और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ इन्द्रियां मानव जीवन को सुख की ओर आग्रसर करती हैं। योग और आयुर्वेद के सायुज्य से व्याधियों का संहार हो जाता है। योग आत्मा और मन का पोषक होकर शरीर को प्रकाशित करता है और आयुर्वेद मन व शरीर के असंतुलन को नष्ट करके मानव को रोगमुक्त करता है। योग और आयुर्वेद में अद्भुत साम्यता हैं, इन दोनों के सेवन से व्यक्ति को रोगमुक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही भौतिक जीवन में आध्यात्मिक अस्तित्व का ज्ञान होने से वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है और ज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो सकता है। योग प्राण का वह स्फुरण है, जो आत्म विकास की परमोच्च अवस्था उत्पन्न करता है और आयुर्वेद उसकी उपचारात्मक शक्ति है। जो शरीर के विकास के लिए जीवन की प्रणालियों को सुदृढ़ कर देती है। योग और आयुर्वेद, दोनों ईश्वरीय ज्ञान हैं। योग का ज्ञान आदि योगी परम पिता शिव से ऋषिमार्ग से मानव तक पहुंचा और आयुर्वेद का विस्तार ब्रह्मा के द्वारा ऋषियों को प्रदान की गई ज्ञान परंपरा से हुआ। योग और आयुर्वेद को वैदिक ज्ञान वृक्ष की दो शाखाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसकी जड़ों को ऋषियों ने वेदों के गहन अध्ययन और विज्ञान प्रयोगों के अभ्यास से सींचा है। यह गहन ज्ञान शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करे तो निश्चय ही कल्याणकारी है। वस्तुतः सनातन परंपरा की सभी ज्ञान और अभ्यास प्रक्रियाएं मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती हैं और उसके कल्याण के लिए सतत निरंतर कार्य करती हैं। योग और आयुर्वेद भी ईश्वर की वही कल्याणकारी वैदिक व्यवस्था है, जिसे ऋषियों ने हम तक पहुंचाया है। इस प्रकार योग और आयुर्वेद श्वास प्रश्वास से आहार और प्रकृति सान्निध्य से औषधि प्रयोग तक मनुष्य को समग्र रूप से स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। इन दोनों के सायुज्य से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरीर के सब चक्र अपने उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। शरीर की सब नाडियां शुद्ध हो जाती हैं। पंच कोष शोध, कुंडलिनी शक्ति सहित समग्र कल्याण का मार्ग खुल जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में आत्मा के उद्धार का उपदेश करते हुए कहा है कि

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना ॥

अर्थात् मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए और पतन के मार्गसे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु है। गीता के इस उपदेश का पालन करने के लिए सर्वप्रथम शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है और स्वस्थ शरीर में आत्मा और मन भी स्वस्थ रहें, उसके लिए ज्ञान और कर्म का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि शरीर ही धर्म का प्रथम साधन है।

योग और आयुर्वेद के प्रयोगों के नामों में भी साम्यता स्पष्ट करती है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है।

योग के आठ अंग कहे गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। आयुर्वेद के भी आठ अंग कहे गए हैं, जिन्हें अष्टंग आयुर्वेद कहा जाता है।

योग में त्रिगुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के संतुलन के लिए कार्य किया जाता है तो आयुर्वेद में त्रिदोष वात, पित्त कफ के संतुलन के लिए कार्य किया जाता है।

योग में षट्कर्मों का उल्लेख है

धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिः लौकिकी त्राटकं तथा।
कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत् ॥

आयुर्वेद में पंचकर्म को प्रश्रय दिया गया है।

वमनं रेचनं नस्यं निरुहस्वानुवासनम्।
एतानि पञ्चकर्माणि कथितानि मुनीश्वरः ॥

योग में आसनों को स्थान दिया गया है तो आयुर्वेद में व्यायाम को प्रश्रय दिया गया है। आसन और व्यायाम परस्पर आश्रित हैं।

योग में प्राणायाम को प्राण शोधक कहा गया है, जबकि आयुर्वेद में पञ्च प्राण की अवधारणा है।

योग और आयुर्वेद दोनों ही ध्यान, धारणा और समाधि पर साम्यता रखते हैं और दोनों ही पंचमहाभूत के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं।

वस्तुतः योग और आयुर्वेद की चिकित्सा अवधारणाएं शास्त्रों के वचन यत्पिण्डे तत्ब्रह्माण्डे के सूक्ष्म विवेचन पर आधारित हैं। समस्त ब्रह्माण्ड में जो ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा जगत को प्रकाशित कर रही है, वहीं देह को भी प्रकाशित कर रही है। देह भी एक पिण्ड होने के कारण ब्रह्माण्डीय ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। देह और ब्रह्माण्ड सूर्य से संचालित हैं। वह बाह्य जगत में सर्वोत्पादक है और देह में प्राण स्वरूप आत्मा का कारक। वेदों ने सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। वेदों ने तीन प्रकार के रोग कहे हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। जिनके उपचारों की प्रशस्ति भी तीन प्रकार की है। सत्वावजय, युक्तिव्यापाश्रय और दैवव्यापाश्रय। क्योंकि योग और आयुर्वेद दोनों का जन्म वेदों से हुआ है, इसलिए इन दोनों के सायुज्य से लोक कल्याण की साधना संभव है।

अष्टांग योग

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।

1. यम– अष्टांग योग का पहला अंग यम है। **यम्यते नियम्यते चित्त इति यमः**। यह अवांछनीय

कार्यों से मुक्ति दिलाता है, इसलिए यम कहलाता है। कायिक, मानसिक और वाचिक संयम का अभ्यास यम के द्वारा संभव है। यम पांच हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह। अहिंसा के प्रभाव से मन, कर्म और वचन से मनुष्य द्वेष और शत्रुता से मुक्त हो जाता है। वह न स्वयं हिंसा का विचार करता है, न किसी को हिंसा के लिए प्रेरित करता है, न किसी को हिंसा के लिए अनुमोदित करता है। सत्य का आचरण करता है, मन और वाणी एकरस हो जाते हैं। अस्तेय से मन कर्म वचन से परद्रव्य के प्रति लालसा की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। ब्रहचर्य की प्रतिष्ठा होने पर तेजस्वी और अपरिमित शक्ति को प्राप्त हो जाता है और अपरिग्रह द्वारा वह भोग साधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यम का पालन करने वाला साधक सहज भाव को प्राप्त होता है तो रोग स्वयं ही दूर हो जाते हैं और मानव आनन्द को प्राप्त हो जाता है।

2. नियम– नियम भी पांच ही हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम कहे गए हैं। शौच अर्थात शुद्धि, पवित्रता। जिसमें बाह्य और आंतरिक शुद्धि करने का नियम है। शारीरिक शुद्धि और वाचिक शुद्धि बाह्य शुद्धि है और मानसिक शुद्धि आन्तरिक शुद्धि है। शुद्ध मन और शुद्ध तन में कोई रोग नहीं पनप सकेगा। संतोष प्राप्त होने पर मनुष्य जीवन के उतार चढ़ावों से प्रभावित नहीं होता है और वह सुख दुःख में समान व्यवहार में रहता है। अन्तःकरण की सन्तुष्टि सन्तोष का लक्षण है। शुचिता और सन्तोष को तप के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उचित अभ्यास से शरीर, प्राण, इन्द्रियों और मन को नियन्त्रित करना तप है। जिसका सम्बन्ध स्वाध्याय से है। स्वाध्याय से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इन सबके साथ ईश्वर का शरणागत होना सभी कष्टों का निवारण कर देता है।

3. आसन– आसन योग का तीसरा अंग है और इसमें विभिन्न शारीरिक मुद्राएं सम्मिलित हैं। जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। आसन की सिद्धि से सभी प्रकार के द्वंद अर्थात शीत, गर्मी, भूख प्यास, हर्ष और विषाद का आघात नहीं होता है। यह समग्र स्वास्थ्य का लक्षण है।

4. प्राणायाम– प्राणायाम योग का चौथा अंग है और इसमें विभित्र श्वास-प्रश्वास की तकनीकी का विशेष प्रयोग होता है, जो प्राण (जीवन ऊर्जा) को नियंत्रित करने में सहायक होता है। प्राणायाम का का कार्य वायवीय शक्ति पर नियंत्रण पाना है। यह समस्त ब्रह्माण्ड वायु से परिपूर्ण है। प्राण का विस्तार तभी सम्भव है, जब श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण हो जाए। प्राणायाम की सिद्धि से धारणा की योग्यता उत्पन्न होती है।

5. प्रत्याहार– प्रत्याहार योग का पंचम अंग है, इसमें इंद्रियों को नियंत्रित करने और उन्हें बाहरी वस्तुओं से हटाकर आंतरिक जागरूकता पर केंद्रित करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। विषयमुक्त इंद्रियां चित्त की चंचलता, चपलता को नष्ट कर देती हैं।

6. धारणा– मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने की प्रक्रिया धारणा कहाती है। यह चित्त की स्थिरता का प्रतीक है और इसकी सिद्धि से ध्यान का मार्ग प्रशस्त होता है।

7. ध्यान– ध्येय का निरन्तर मनन ही ध्यान है। गहन एकाग्रता और मन की स्थिरता की अवस्था ही ध्यान का लक्षण है, जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। ध्यान सिद्धि से अहंभाव नष्ट हो जाता है। जो पूर्ण निरोगता का प्रभाव उत्पन्न करता है।

8. समाधि– योग के समस्त सूत्र अन्त में समाधि पर ही प्रगट होते हैं। यह साधना की चरम अवस्था है। इसमें द्वैतभाव भी नष्ट हो जाता है। यही जीवन का परम उत्कर्ष होता है। मनुष्य पूर्ण आत्मजागृति से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है।

इस प्रकार योग के आठ अंग मनुष्य को पूर्ण स्वस्थ और जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होते हैं।

अष्टांग आयुर्वेद

योग की भांति आयुर्वेद के भी आठ मुख्य अंग हैं, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा और स्वास्थ्य को समझने में सहायता करते हैं। ये आठ अंग हैं...

1. काय चिकित्सा: चीयते प्रशस्तदोषधातुमलैः इति कायः। काय चिकित्सा अग्नि के संतुलन की चिकित्सा है। आयुर्वेद में अग्नि महत्वपूर्ण महाभूत है। जिसके उपयोग से शरीर की प्रत्येक कोशिका को शुद्ध करने की प्रकिया काय चिकित्सा है। शरीर में अग्नि संतुलन से त्रिदोष और सप्तधातु संतुलित होती हैं।

इस विधि में ज्वर, रक्तपित्त, शोथ, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह और अतिसार आदि रोगों की औषधिप्रयोग द्वारा चिकित्सा की जाती है। आमाशय तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले रोगों की शान्ति का उपाय किया जाता है। अतः कायचिकित्सा कहा जाता है।

2. भूतविद्या– मानसिक रोगों की चिकित्सा में भूत विद्या की भूमिका महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में बैक्टीरिया और जीवाणुओं को राक्षस, पिशाच, असुर आदि नामों से पुकारा जाता है। हमारे शरीर में होने वाले अनेक रोग इन्हीं बैक्टीरिया और जीवाणुओं के कारणहोते हैं।

3. शल्य चिकित्सा– किसी शस्त्राघात या चोट लगने या गंभीर घाव होने पर शल्य चिकित्सा की आश्यकता होती है। शल्य चिकित्सा आयुर्वेद का महत्वपूण अंग है जो शस्त्र आदि के द्वारा किया जाता है।

4. शालाक्य तंत्र– गले और गले के ऊपर स्थित सभी अंगों जैसे कि मुंह, नाक, कान, आंख आदि से जुड़ी समस्याओं का निदान शालाक्य तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें शलाका द्वारा चिकित्सा की जाती है।

5. अगद तंत्र– विषों की परीक्षा और उसके दुष्प्रभावों की चिकित्सा अगद तंत्र के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद के अनुसार विषाक्त पौधों और विषाक्त खनिज, जीव जंतुओं सांप-बिच्छू आदि के विष की चिकित्सा इस पद्धति से होती है।

6. रसायन तंत्र– रस और धातुओं शोधन के बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है इसलिए रसों और धातुओं का असंतुलन शरीर में जो रोग उत्पयन करते हैं। इनकी चिकित्सा रसायन तंत्र के अंतर्गत की जाती है।

7. वाजीकरण तंत्र– शरीर के प्रजजन तंत्र के रोगों की चिकित्सा वाजीकरण चिकित्सा कहाती है। जिसके अन्तर्गत नपुंसकता आदि की चिकित्सा की जाती है, जो प्रजनन स्वास्थ्य और कामशक्ति को बढ़ाने से संबंधित है।

8. कौमारभृत्य– कौमारभृत्य बाल चिकित्सा को कहा जाता है। जो बच्चों के रोगों की चिकित्सा से संबन्धित है।

पोल्का डॉट साड़ी से बनाएं खूबसूरत ड्रेस, लगेंगे क्लासी और खूबसूरत

आपके पास भी इस तरह की पोल्का डॉट साड़ी हैं और अब इन साड़ियों को आप नहीं पहनती हैं। तो आप इन साड़ियों के इस्तेमाल से डिजाइनर ड्रेस तैयार कर सकती हैं। ऐसे में आप इन ड्रेसेज को पहनकर काफी खूबसूरत लगेंगी।

आजकल पोल्का डॉट साड़ी काफी चलन में हैं। ऐसे में ज्यादातर महिलाओं के पास यह साड़ी देखने को मिल जाएगी। हालांकि दो-तीन बार एक साड़ी को पहनने के बाद ज्यादातर महिलाएं इन्हें किसी और को दे देती हैं या फिर उस साड़ी को फेंक देती हैं। ऐसे में आपके पास भी इस तरह की पोल्का डॉट साड़ी हैं और अब इन साड़ियों को आप नहीं पहनती हैं। तो आप इन साड़ियों के इस्तेमाल से डिजाइनर ड्रेस तैयार कर सकती हैं। ऐसे में आप इन ड्रेसेज को पहनकर काफी खूबसूरत लगेंगी। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको पोल्का साड़ी से बनने वाली ड्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं।

पोल्का डॉट वन शोल्डर मिडी ड्रेस

अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पोल्का डॉट साड़ी है। तो इसका इस्तेमाल करके पोल्का डॉट वन शोल्डर मिडी ड्रेस तैयार कर सकती हैं। इस ड्रेस के साथ मेकअप, एक्सेसरीज और हील्स भी शामिल कर सकती हैं। इस ड्रेस को पहनकर आपका लुक गॉर्जियस लगेगा।

प्रिंटेड फिट एंड फ्लायर ड्रेस

आप किसी भी पोल्का डॉट साड़ी के इस्तेमाल से प्रिंटेड फिट एंड फ्लायर ड्रेस बना सकती हैं। इस ड्रेस को आप किसी भी फंक्शन में भी जा सकती हैं। आप टेलर की मदद से या खुद से इसको अपनी साइज के हिसाब से बनवा सकती हैं। वहीं मेकअप और हेयर स्टाइल से अपने लुक की खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं।

नेवी ब्लू पोल्का डॉट प्रिंटेड ड्रेस

अगर आप भी भीड़ से हटकर नजर आना चाहती हैं तो आप पोल्का डॉट साड़ी का इस्तेमाल कर नेवी ब्लू पोल्का डॉट प्रिंटेड ड्रेस तैयार करवा सकती हैं। यह आपके लुक में चार चांद लगाने का काम करेगा। वहीं आप चाहें तो इस ड्रेस को घर पर भी तैयार कर सकती हैं। आप इस ड्रेस को पहनकर क्लासी और मॉर्डन लुक क्रिएट कर सकती हैं।

पोल्का डॉट लेयर्ड मिडी ड्रेस

आप चाहें को अपनी किसी भी पोल्का डॉट साड़ी का इस्तेमाल कर पोल्का डॉट लेयर्ड मिडी ड्रेस को बना सकती हैं। इसको पहनकर आप किसी खूबसूरत हसीना से कम नहीं लगेंगे। यह रेट्रो लुक की तरह है, जिसको आप रीक्रिएट कर 90२ की अभिनेत्री की तरह दिख सकती हैं। आपके इस लुक को देखकर घर में मौजूद सभी लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे।

समाज की रीढ़ मानी जाती थीं पारिवारिक परंपराएं

वैदिक काल में पारिवारिक परंपराएँ समाज की रीढ़ मानी जाती थीं। परिवार को कुल कहा जाता था और यह वैदिक समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। उस समय परिवार पितृ-सत्तात्मकहोते थे, यानी परिवार का मुखिया पुरुष होता था, जिसे गृहपति कहा जाता था। गृहपति न केवल परिवार के आर्थिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाता था, बल्कि धार्मिक क्रियाकलापों का संचालन भी करता था। वैदिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित धर्म और कर्तव्य निर्धारित था, जिसे पालन करना उसका नैतिक दायित्व माना जाता था।

विवाह एक महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार था, जिसे केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक दायित्व के रूप में देखा जाता था। विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ संपन्न किया जाता था। विवाह के बाद स्त्रियाँ पति और ससुराल के प्रति समर्पित रहती थीं और घरेलू कार्यों के साथ-साथ धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाती थीं। उन्हें परिवार की संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया था। शिक्षा भी पारिवारिक परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा थी। बच्चों को प्रारंभ में माता-पिता से नैतिक शिक्षा दी जाती थी, और बाद में पुत्रों को गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ वे गुरु के संरक्षण में वेदों, संस्कारों और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करते थे। उपनयन संस्कार के माध्यम से बालक को विद्यारंभ के लिए तैयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त, परिवार में अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्कार होते थे जैसे - नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। पूर्वजों का सम्मान श्राद्ध के माध्यम से किया जाता था। हर दिन सूर्य और अग्नि की पूजा, ऋतु-पर्याय त्योहारों का आयोजन, यज्ञ और हवन, ये सभी पारिवारिक परंपराओं का हिस्सा थे।

विवाह एक महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार था, जिसे केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक दायित्व के रूप में देखा जाता था। विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ संपन्न किया जाता था।

इन परंपराओं ने न केवल वैदिक समाज में अनुशासन और नैतिकता को बनाए रखा, बल्कि परिवारों को एकजुट और सुसंस्कृत बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हमारा समाज में नैतिकता का बहुत तेजी से अवमूल्यरन हो रहा है, ऐसे में वैदिक काल से न केवल प्रेरणा लेने की आवश्यककता है बल्कि उन परंपराओं को आज अनुसरण करने की भी जरूरत महसूस हो रही है।

देहरादून में करना चाहते कुछ तूफानी तो जरूर एक्सप्लोर करें ये जगहें

अगर आप देहरादून में ऐसी जगहों की तलाश करना चाहते हैं, जहां पर कुछ अच्छी एक्टिविटी कर सकें। अगर आप भी देहरादून में कुछ तूफानी करना चाहते हैं, तो आपको आसपास के हिल स्टेशन पर घूमने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

समीर मलिक

देहरादून एक ऐसी जगह है, जहां पर आपको खूबसूरत हिल स्टेशन मिलेंगे। यहां से हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और धनोल्टी जैसी कई जगहों पर आप जा सकते हैं। वहीं अगर आप देहरादून में कुछ रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं। वहीं कुछ देहरादून में ऐसी जगहों की तलाश करना चाहते हैं, जहां पर कुछ अच्छी एक्टिविटी कर सकें। अगर आप भी देहरादून में कुछ तूफानी करना चाहते हैं, तो आपको आसपास के हिल स्टेशन पर घूमने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको देहरादून की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

रॉबर्स केव देहरादून

देहरादून की यह आपको काफी रोमांचक लगेगी। क्योंकि इसकी बनावट लोगों को आकर्षित करती है। जिन लोगों ने पहले कभी गुफा वाली जगहों पर प्रवेश नहीं किया है, उनके लिए यह एडवेंचर्स साबित हो सकता है। क्योंकि यहां पर आपको पैदल जाना होगा। पैरों में पानी होता है और मछलियां आपके पैरों को छूती हैं। हालांकि शुरूआत में आपको गुफा में चलने में थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे अंदर जाते ही नॉर्मल लगने लगेगा। प्रयास करें कि आप सुबह-सुबह पहुंचें, क्योंकि यहां पर बहुत भीड़ लगती है। यह मसूरी के पास घूमने लायक अच्छी जगहों में से एक है।

रॉक क्लाइबिंग

अगर आप कुछ तूफानी करना चाहते हैं और बिना किसी सहारे के पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं। तो आपको देहरादून में रॉक क्लाइंबिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। यह सालन गांव में रॉक क्लाइबिंग करवाई जाती है। जहां पर आपको हर दिन भीड़ देखने को मिलेगी। आप यहां पर कैंपिंग के साथ कई तरह की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वहीं आप यहां पर पैकेज भी बुक कर सकते हैं और पूरा रात टेंट में बिता सकते हैं। इस दौरान आपको मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना होगा और पूरी लाइफ कैंप की तरह जीना होगा। यह आपके लिए एक रोमांचक अनुभव हो सकता है।

मालसी डियर पार्क

अगर आप देहरादून में कुछ रोमांचक करना चाहते हैं, तो मालसी डियर पार्क जा सकते हैं। क्योंकि यह जगह आपको निराश नहीं करेगी। आप यहां पर जिप लाइनिंग और तरह-तरह की एक्टिविटी भी कर सकेंगे। बच्चों को भी यहां पर एक्टिविटी करवाई जाती है। वहीं अगर आप छोटा ट्रिप प्लान कर रही हैं, तो आपको यहां पर आपको भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। यह देहरादून के पास घूमने वाली बेस्ट जगहों में से एक है।

यूपी में पर्यटन को और लगेंगे पंख, राष्ट्रीय स्तर की संभावनाओं से मिल रहे पुख्ता संदेश

पर्यटन के साथ सुधरेगी अर्थव्यवस्था, बढ़ेंगे रोजी-रोजगार के अवसर

योगी सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में यूपी में पर्यटन को और पंख लगेंगे। द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के परिदृश्य के बारे में जो पूवार्नुमान जताया है उससे तो इस बात के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। इन संकेतों में छिपी संभावनाओं को सच में तब्दील करने को योगी सरकार पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से प्रतिबद्ध भी है। प्रदेश में विदेशी और घरेलू पर्यटकों की आमद बढ़ने के साथ ही इनके द्वारा यात्रा, रहने, खाने और यादगार के रूप में स्थानीय उत्पादों के खरीदे जाने से अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी ही, इससे जुड़े ट्रांसपोर्टेशन, होटल, होम स्टे, गाइड आदि सेक्टर्स में रोजी-रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

डब्ल्यूटीटीसी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 के राष्ट्रीय पर्यटन संबंधी आंकड़े 2019 के सभी मानकों को पीछे छोड़ चुके हैं। संस्था ने 2030 तक के लिए जो पूवार्नुमान जताए हैं वे बेहद ही संभावनाओं वाले हैं। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या, राधाकृष्ण की जन्मभूमि और कर्मस्थली ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश में ही है। तीरथराज प्रयाग, विश्व की सबसे पुरातन नगरी एवं तीनों लोकों से न्यारी शिव की काशी, दुनिया को शांति और अहिंसा के संदेश से प्रकाशित करने वाले भगवान बुद्ध से जुड़े सभी प्रमुख स्थल कुशीनगर, सारनाथ, कपिलवस्तु भी उत्तर प्रदेश में हैं। इन सब वजहों से देश में बढ़ते पर्यटन के कारण यूपी में पर्यटन की संभावना भी बढ़ जाती है। यह हो भी रहा है। सरकारी आंकड़े इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं।

ऐसा हो इसके लिए संभावना वाले टूरिज्म स्पॉट को केंद्र बनाकर योगी सरकार पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है। प्राथमिकता बनाकर चरणबद्ध तरीके से यह काम हो भी रहा है। इसमें केंद्र सरकार का भी विभिन्न योजनाओं के जरिये भरपूर सहयोग मिल रहा है। डब्ल्यूटीटीसी के अनुसार देश के लिए पर्यटन के लिहाज से साल 2025 रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है। इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर का योगदान 22 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इस पूवार्नुमान के अनुसार टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सेक्टर्स में रोजगार पाने वालों की संख्या 48 मिलियन से अधिक हो सकती है। संस्था की ओर से साल 2030 के लिए जताए गए पूवार्नुमान के अनुसार पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मिलने वाला योगदान 42 लाख करोड़ और रोजगार बढ़कर 64 मिलियन हो जाएगा। इन आंकड़ों में ही उत्तर प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर की भी संभावनाएं छिपी हैं। खासकर धार्मिक पर्यटन के लिहाज से।

सरकार भी इसे जानती और स्वीकार करती है। इसीलिए ऐसे स्थलों के विकास पर उसका सर्वाधिक फोकस भी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, 'धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के प्रयास न केवल आस्था को आह्लादित करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन, प्रसाद तथा रामायण, कृष्ण, बौद्ध सर्किट जैसी योजनाओं ने पर्यटन विकास को गति दी हैं। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने इन क्षेत्रों में सड़क, परिवहन, रुकने की सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए है। पर्यटन के प्रति बढ़ते रुझान और सरकार की प्रभावशाली नीतियों के चलते प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजी-रोजगार के अवसर बढ़े हैं। स्थानीय हस्तशिल्प एवं स्थान विशेष की पहचान बने उत्पादों को खूब लाभ मिला है। इन पर्यटन स्थानों में हुए विकास से युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को भी नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। निःसंदेह उत्तर प्रदेश ने अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित एवं पुनरुद्धार कर पर्यटन के नए हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है'।

मानसिक शांति को प्रभावित करती सोशियल डंपिंग

मनोविज्ञानियों के सामने आज इमोशनल डंपिंग बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। बदलते सामाजिक परिवेश में इमोशनल डंपिंग का दायरा बढ़ता जा रहा है तो लोग इमोशनल डंपिंग के आसानी से शिकार भी होते जा रहे हैं।

दरअसल आज अपनी समस्याओं का बोझ दूसरे पर लादने का दौर चल निकला है। खासतौर से सोशियल मीडिया का अधिकतम उपयोग आज इसी काम में होने लगा है। डिजिटलीय भाषा में कहो जाएं तो यह दौर इमोशनल डंपिंग का चल निकला है। कहने को तो यह कहा जाता है कि यदि आप किसी परेशानी में हो तो मन को हल्का करने के लिए अपनी

अरुण मिश्रा

समस्या को किसी संगी साथी से साझा करलें, इससे दो लाभ है एक तो तनाव से तात्कालीक मुक्ति मिल जाती है दूसरी और हो सकता है कि सामने वाला कोई सकारात्मक हल निकाल दें। पर कहा यह भी जाता है कि अपना दुख दर्द उसी से साझा करें जो आपके प्रति गंभीर हो। आपके दुख दर्द को सुनकर सहानुभूति के स्थान पर आपको मजाक का कारण तो नहीं बना दे। इमोशनल डंपिंग इससे थोड़ी अलग स्थिति है और आज यह बड़ी समस्या के रुप में सामने आ रही है। होने यह लगा है कि अपने मन

मस्तिष्क का बोझ हम आसानी से दूसरे पर ड़ाल देते हैं। यह भी नहीं सोचा जाता है कि जिससे आप साझा कर रहे हैं वह इस स्थिति में है भी नहीं कि आपकी समस्या के प्रति कुछ कर सके। हो तो यह रहा है कि हम हमारे किस्से, दुख, तकलीफ या अन्य अच्छे बुरे समाचार मोबाइल, वाट्सएप, इंस्टाग्राम, शार्टस या इसी तरह के किसी अन्य माध्यम से दूसरे पर थोप देते हैं और जाने-अनजाने में दूसरा व्यक्ति इमोशनल डंपिंग का शिकार हो जाता है। आज हालात तेजी से गदलते जा रहे हैं।

मनोविज्ञानियों के सामने आज इमोशनल डंपिंग बड़ी समस्या के रुप में सामने आ रहा है। बदलते सामाजिक परिवेश में इमोशनल डंपिंग का दायरा बढ़ता जा रहा है तो लोग इमोशनल डंपिंग के आसानी से शिकार भी होते जा रहे हैं। हांलाकि हमारे यहां माना जाता रहा है कि कहने से दुख घटता है पर यह भी कहा जाता है कि अपनी दुख तकलीफ उसे सुनाओं जो सुन सके। आज का दौर लगभग उलटा होता जा रहा है हम हमारी दुख तकलीफ या हमारी बात किसी पर थोपने के लिए उसकी और विभिन्न माध्यमों से धकेल देते हैं और अब समस्या सामने वाले की हो जाती है। दूसरे की मनोस्थिति व परिस्थितियों को समझने की कोशिश ही नहीं होती। यह हालात ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते और इसके नकारात्मक परिणाम अधिक आने लगे हैं। इमोशनल डंपिंग में दरअसल जो श्रोता है वह प्रभावित होता है।

मनोविज्ञानी डॉ. रैडल टर्नर का मानना है कि इमोशनल डंपिंग आज समाज को नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित कर रही है। आज संप्रेषण या संवाद के विभिन्न माध्यमों से हम अपनी भड़ास निकाल लेते हैं और सामने वाले की मनोस्थिति को समझने का प्रयास ही नहीं करते। अगला व्यक्ति इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके पास आपकी भड़ास सुनने का समय भी है या नहीं, या आपकी भड़ास का निदान कर सकता है या नहीं आपकी समस्या से जूझने की क्षमता भी है या नहीं। यह अपने आपमें एक समस्या हो जाती है। इमोशनल डंपिंग देखा जाए तो पूरी तरह से नकारात्मक और एकतरफा तरीका है और यह आज इस कदर हाबी हो गया है कि आसानी से आज व्यक्ति इससे दो चार हो रहे हैं। दरअसल सामने वाले व्यक्ति को हम आउटलेट समझ कर उसके साथ व्यवहार करते हैं।

कहीं वह अपने आपको अपराधी जैसा समझने लगता है। एक तरह से सामने वाला व्यक्ति आब्जेक्ट के रुप में मानने लगते हैं। उसकी परिस्थितियों और वह आपकी बात से साझा होना भी चाहता है या नहीं उससे इमोशनल डंपिंग करने वाले को कोई लेना देना नहीं रहता। यह नए जमाने की नई तरह की समस्या बनती जा रही है। सोशियल मीडिया पर जब इस तरह की चीजें साझा की जाती है तो सामने वाले के साथ आपका भावनात्मक संबंध भी नहीं होता, ऐसे में सामने वाला थोड़ा संवेदनशील है तो एक तरह के तनाव से गुलरने लगता है। सोचता है ऐसा कैसे हो गया। क्या कारण रहे। या इसका समाधान तो आसानी से हो सकता है या अन्य किसी तरह से सोच सकता है। पर इस तरह का इमोशनल डंपिंग सामने वाले व्यक्ति पर नकारात्मकता के भाव पैदा करता है और वह कभी कभार तनाव के दौर से गुजरने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई दिल पर मत लो। अब जब दिल पर मत लो की भावना होगी तो फिर आपकी भड़ास के मायने क्या रहेंगे।

इमोशनल डंपिंग का सीधा सीधा मतलब यह है कि अपनी बात डंप करते समय या यों कहें कि साझा करते समय सामने वाले की मनोदशा, सहमति, असहमति, समय, विषय या अन्य से डंप करने वाले को कोई लेना देना नहीं रहता और आज यही हो रहा है। ऐसे में इमोशनल डंपिंग के शिकार लोगों के प्रति मनोविज्ञानी गंभीर चिंतन मनन में लगे हैं।

वहीं इग्नोर करने, दूसरी बातों में ध्यान लगाने, अवसर मिलने पर सामने वाले को असहमति से अवगत कराने और उसे अनावश्यक संवाद के लिए इशारों में मना करने की हिम्मत भी जुटानी होगी क्योंकि दूसरे को मुसिबत में सहायता कोई बात साझा करने में और इक तरफा भड़ास निकालने में अंतर होता है। स्वयं तनाव के बोझ से मुक्त होने के लिए दूसरे को तनाव में ड़ालना किसी भी हालात में उचित नहीं माना जा सकता। नहीं तो जिस तेजी से आज इमोशनल डंपिंग का दौर चला है वह आने वाले समय में और भी अधिक गंभीर और समाज के लिए नकारात्मकता फैलाने वाला हो जाएगा।

ऐसे में सोशियल मीडिया के उपयोग के समय उसमें रम जाने की मानसिकता को छोड़ना होगा। रील्स या शार्टस में प्रस्तुत सामग्री के प्रति अधिक गंभीर होने की आवश्यकता नहीं रह जाती है क्योंकि उसके समय व विश्वसनीयता प्रश्नों के घेरे में हमेशा बनी रहती है। एक तरह से यह तो भावनात्मक ब्लेकमेलिंग का माध्यम बनता जा रहा है। दूसरा यह कि जो सामग्री आपको विभिन्न प्लेटफार्म से मिल रही है उसे गंभीरता से लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि उस सामग्री पर प्रतिक्रिया के चक्कर या प्रतिक्रियाओं के चक्रव्यूह में फंसने से आपमी मानसिक शांति भंग होना स्वाभाविक है। इसलिए दिमाग पर अधिक बोझ ड़ालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

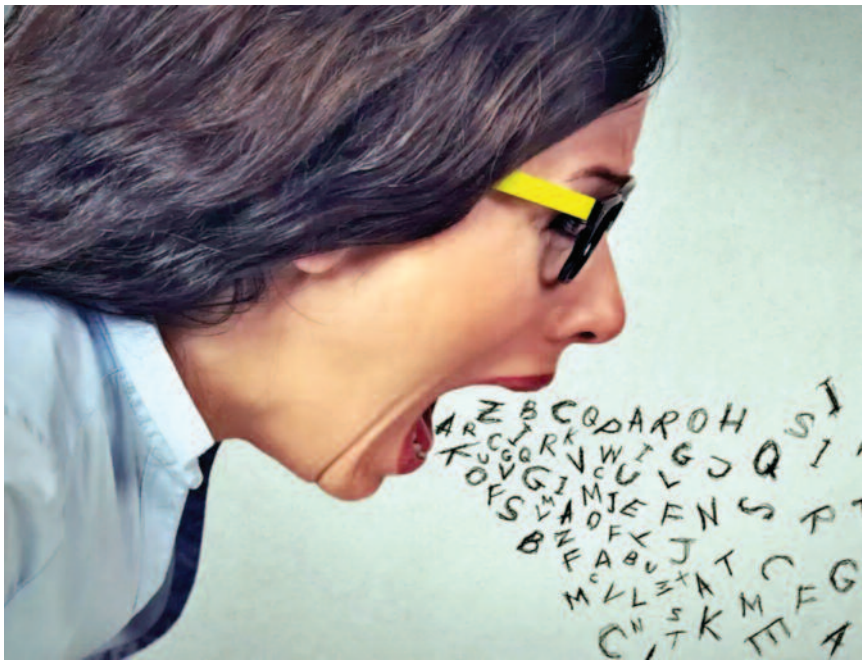

क्या आम खाने से बढ़ता है पिंपल्स-छाले का खतरा

डॉ. निमित त्यागी

गर्मियों के मौसम में 'फलों का राजा' आम आने लगता है। आम खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है। क्योंकि यह रसीला फल न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि यह पोषण से भी भरपूर होता है। आम में विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं। जोकि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग 2-3 आम खाने के बाद या लगातार कुछ दिन आम खाते हैं, तो उनके फेस पर पिंपल्स यानी की मुंहासे निकल आते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या वाकई आम खाने से स्किन को नुकसान पहुंच सकता है।

आम खाने से मुंहासे निकलना

हालांकि इस बाद का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जो यह साबित करे कि आम खाने से पिंपल्स की समस्या होती है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से आम खाने से स्किन पर पिंपल्स हो सकते हैं।

पिंपल्स निकलने का कारण

बता दें कि आम के छिलके और रस में 5-रेसोर्सिनॉल नामक केमिकल पाया जाता है। जोकि स्किन पर लगने से पिंपल्स जैसे निशान बना सकता है। वहीं यह मुंह में जाने पर स्टोमेटाइटिस यानी की जलन और छोटे-छोटे घाव हो सकते हैं।

हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स

- आम का GI लेवल ज्यादा होता है।
- जिससे शुगर और इंसुलिन लेवल तेजी से बढ़ता है।
- आम खाने से सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है।
- इससे स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जोकि मुहांसे का कारण बन सकते हैं।

केमिकल से पके आम

कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए आम खाने से एसिटिलीन गैस बनती है। इस गैस की वजह से मुंह में छाले या फिर जलन की समस्या हो सकती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति में विटामिन की कमी है, तो आम खाने से मुंह में छाले हो सकते हैं।

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए आम

- डायबिटीज के मरीज
- मोटापे से जूझ रहे लोगों को
- पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को
- स्किन एलर्जी वाले लोगों को
- किडनी मरीजों को
- 4 साल से कम उम्र के बच्चों को

किन चीजों के साथ न खाएं आम

- अगर आप खट्टे फलों के साथ आम का सेवन करते हैं, तो आपके पाचन में गड़बड़ी हो सकती है।
- मसालेदार खाने के साथ आम का सेवन नहीं करना चाहिए।
- दही के साथ भी आम का सेवन नहीं करना चाहिए।
- शराब आदि के साथ आम नहीं खाना चाहिए।
- आम खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए।

पानी में भिगाएं आम

आम खाने से पहले हमेशा इसको 2-3 घंटे ताजे पानी में भिगोकर रखना चाहिए। इससे इसमें मौजूद फाइटिक एसिड और कीटनाशक हट जाते हैं। यह न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण और पाचन में बाधा बन सकते हैं।

ठंडा आम न खाएं

फ्रिज से निकालकर फौरन ठंडा आम खाने से बचना चाहिए। इससे गले में खराश या पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। इसे सामान्य तापमान में कुछ देर के लिए रखना चाहिए।

खाली पेट न खाएं

कभी भी खाली पेट आम नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इससे आपको एसिडिटी हो सकती है। इसलिए कुछ खाने के बाद ही इसको खाना बेहतर है।

शुद्ध और पका आम खाएं

मार्केट से आम खरीदने के दौरान ध्यान रखें कि वह कार्बाइड से पका हुआ न हो। क्योंकि ऐसा आम खाने से आपके शरीर से नुकसान पहुंच सकता है।

पानी में भिगोकर आम खाना फायदेमंद

आम में फाइटिक एसिड पाया जाता है, जो एक एंटी-न्यूट्रिएंट होता है। यह शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। वहीं जब आप 2-3 घंटे पानी में भिगोते हैं, तो इससे फाइटिक एसिड कम हो जाता है। वहीं शरीर को भी आम से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलते हैं। आम में मौजूद फाइटोकेमिकल्स भी कम हो जाते हैं। जिससे नेचुरल फैट बस्टर की तरह काम करता है। वहीं आम को भिगोने से इस पर लगे कीटनाशक, धूल-मिट्टी और गंदगी भी हट जाती है। जिससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

रोजाना कितने आम खाएं

यह आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आमतौर पर रोजाना एक मध्यम आकार का आम खाना सबसे बेहतर है। इससे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इससे ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है और इससे मुंहासों या शुगर स्पाइक्स का खतरा कम होता है।

कैसे ठीक करें पिंपल्स

अगर आम खाने से पिंपल्स की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में आम कम मात्रा में खाना चाहिए। खासकर अगर आपकी त्वचा मुंहासों के प्रति सेंसिटिव है, तो खूब पानी पिएं, बैलेंस्ड डाइट लें और हाई ग्लाइसेमिक फूड्स से बचना चाहिए। फेस को साफ रखने के लिए जेंटल क्लींजर का इस्तेमाल करें और सूजन को कम करने का प्रयास करने की कोशिश करें।

वहीं अगर पिंपल्स अधिक हो जाएं, तो डमेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।

श्रेया घोषाल

विभिन्न भाषाओं में 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ भारत की नंबर 1 गायिका

आकांशा गर्ग

विश्व संगीत दिवस पर, जब पूरी दुनिया संगीत की सार्वभौमिक भाषा का जश्न मनाने के लिए एक साथ आती है, भारत गर्व से एक ऐसी आवाज पर प्रकाश डालता है जिसने पीढ़ियों को परिभाषित किया है- श्रेया घोषाल। दशकों से उत्कृष्टता के साथ, दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों और शैलियों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैली एक सूची के साथ, वह भारत की निर्विवाद नंबर 1 गायिका और भारतीय संगीत इतिहास में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त गायिकाओं में से एक बनी हुई हैं।

जबकि उनके चार्ट-टॉपर्स बहुत हैं, जो उनकी विरासत को वास्तव में मजबूत करता है वह एक दुर्लभ और शक्तिशाली उपलब्धि है - विभिन्न भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यह केवल प्रतिभा का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उनकी आवाज संस्कृतियों, राज्यों और ध्वनियों के पार भारतीय संगीत के ताने-बाने में कितनी गहराई से बुनी हुई है। यहाँ उन मील के पत्थरों पर एक नजर है जिसने उन्हें एक राष्ट्रीय खजाना बना दिया है:

1. 2002 - 'बैरी पिया' (देवदास)

विश्व संगीत दिवस पर, जब पूरी दुनिया संगीत की सार्वभौमिक भाषा का जश्न मनाने के लिए एक साथ आती है, भारत गर्व से एक ऐसी आवाज पर प्रकाश डालता है जिसने पीढ़ियों को परिभाषित किया है- श्रेया घोषाल। दशकों से उत्कृष्टता के साथ, दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों और शैलियों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैली एक सूची के साथ, वह भारत की निर्विवाद नंबर 1 गायिका और भारतीय संगीत इतिहास में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त गायिकाओं में से एक बनी हुई हैं। जबकि उनके चार्ट-टॉपर्स बहुत हैं, जो उनकी विरासत को वास्तव में मजबूत करता है वह एक दुर्लभ और शक्तिशाली उपलब्धि है - विभिन्न भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यह केवल प्रतिभा का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उनकी आवाज संस्कृतियों, राज्यों और ध्वनियों के पार भारतीय संगीत के ताने-बाने में कितनी गहराई से बुनी हुई है। यहाँ उन मील के पत्थरों पर एक नजर है जिसने उन्हें एक राष्ट्रीय खजाना बना दिया है:...

2. 2005 - 'धीरे जलना' (पहेली)

इस रहस्यमयी रोमांटिक ट्रैक में, उनकी आवाज धीमी गति से जलती हुई मोमबत्ती की तरह बजती है - सुरुचिपूर्ण, प्रेतवाधित और तीव्र। एम. एम. कीरवानी द्वारा रचित, यह गीत अपनी स्तरित रचना के लिए अलग था, लेकिन यह श्रेया की आवाज थी जिसने इसे स्थायी गहराई दी

3. 2007- 'ये इश्क हाय' (जब वी मेट)

शास्त्रीय संगीत से समकालीन संगीत की ओर एक बड़ा बदलाव, इस जीवंत, उच्च-ऊर्जा वाले लोकगीत-सूफी गीत ने उनकी बेजोड़ रेंज को दिखाया। उनके आकर्षक स्वर गीत (करीना कपूर) की भावना से मेल खाते थे, जिसने गीत को सांस्कृतिक उन्माद में बदल दिया और उन्हें तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया।

4. 2008 - 'फेरारी मॉन' (अंतहीन) बंगाली

अपनी जड़ों की ओर बढ़ते हुए, 'अंतहीन' का यह बंगाली ट्रैक विशुद्ध कविता था। उनकी आवाज व्यवस्था के माध्यम से धीरे-धीरे बहती है, अकेलेपन, लालसा और नाजुक प्यार को व्यक्त करती है - सब कुछ फुसफुसाते हुए। अतिसूक्ष्मवाद में एक उत्कृष्ट कृति।

5. 2008 - 'जीव रंगला' (जोगवा)

सामाजिक-सांस्कृतिक विषयों पर आधारित भावनात्मक रूप से आवेशित ट्रैक, इस मराठी गीत ने एक बार फिर उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया। उच्चारण पर उनकी पकड़, अभिव्यक्ति की गहराई और त्रुटिहीन स्वर-विन्यास ने दिखाया कि भाषा कभी भी बाधा नहीं बनी।

6. 2021 - 'मायावा छायावा' (इरावीन निजहाल)

उनकी पांचवीं जीत ए.आर. रहमान द्वारा रचित एक गहन प्रयोगात्मक तमिल ट्रैक से मिली। श्रेया के अलौकिक स्वरों में सिनेमाई जटिलता की परतें थीं, जिसने गीत को एक अलौकिक बनावट दी। इसने उनके कलात्मक विकास को चिह्नित किया और उनकी अखिल भारतीय स्थिति की पुष्टि की।

अपने शास्त्रीय संगीत की शुरूआत से लेकर शैली और भाषा की सीमाओं को तोड़ने तक, श्रेया घोषाल भारत में पार्श्व गायन का स्वर्ण मानक बनी हुई हैं। सैकड़ों पुरस्कारों, एक दर्जन से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित गीतों और प्रशंसकों के दिलों में एक अडिग जगह के साथ, उनका सफर किसी किंवदंती से कम नहीं है।

जैसा कि विश्व विश्व संगीत दिवस मना रहा है, भारत अपनी सबसे दिव्य आवाज, राष्ट्र का गौरव - श्रेया घोषाल का जश्न मना रहा है, वह आवाज जो हम सभी को एकजुट करती है।

IPL को मिला नया चैम्पियन

कोहली के नाम रही 'विराट' विजय

एक बड़े खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपने करियर में सभी प्रमुख टूर्नामेंट में विजय हासिल करे। विराट की टीम आईपीएल के खिताब से अभी तक वंचित थी। आपको बता दें विराट ने टी-20 और टेस्ट मैचों से संन्यास ले लिया है।

आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम ने आईपीएल-2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। आईपीएल के 18वें सीजन में उसे एक नया चैम्पियन मिल गया है। 17 साल से यह टीम इस खिताब के लिए तरस रही थी। इस टीम के पास विराट कोहली जैसा खिलाड़ी होने के बावजूद आईपीएल का चैम्पियन बनना नसीब नहीं हुआ। एक से एक धाकड़ खिलाड़ी बेंगलुरू की टीम में रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के एबी डीविलियर्स का नाम इसमें लिया जा सकता है। पर, मंगलवार 3 जून को किस्मत चमक गई। सभी ने विराट कोहली को मैदान पर रोते देखा। उनका भावनओं में बहना स्वाभाविक था। एक बड़े खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपने करियर में सभी प्रमुख टूर्नामेंट में विजय हासिल करे। विराट की टीम आईपीएल के खिताब से अभी तक वंचित थी। आपको बता दें विराट ने टी-20 और टेस्ट मैचों से संन्यास ले लिया है। उनका करियर ढलान पर है, ऐसे में यह खिताबी जीत उन्हें कितना सुकून देगी, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है।

यही वजह है कि मैच के बाद सारे खिलाड़ी विराट कोहली को बधाई देने के लिए दौड़ पड़े। डीविलियर्स और कभी बेंगलुरू टीम का हिस्सा रहे क्रिस गेल ने मौजूद रहकर इस पल को और खास बना दिया। हांलाकि, यह जीत केवल 6 रनों से हुई। इसके बावजूद रिकॉर्ड बुक में बेंगलुरू के नाम पहली जीत दर्ज हो गई। पंजाब किंग्स की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया तो इसमें कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा योगदान रहा। एलीमिनेटर-2 में उन्होंने मुंबई इंडियंस को हरा कर पंजाब को फाइनल में पहुंचा दिया। श्रेयस की 87 रनों की नाबाद पारी ने 5 बार की चैम्पियन

मुंबई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड जाने वाली भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर चयनकताओं की आलोचना भी हो रही है।

कई मायनों में खास रहा यह आईपीएल

इस बार का आईपीएल कुछ युवाओं को सामने लाया है। ये भारत का भविष्य हैं। इसमें सबसे पहला नाम बिहार के वैभव सूर्यवंशी का है जिसने 14 साल की उम्र में झंडा गाड़ दिया है। राजस्थान रायल्स की टीम की ओर से उसने पारी की शुरूआत की। एक शतक और एक अर्ध शतक के साथ उसका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। वैभव ने अपनी साहसिक बल्लेबाजी से बहुत प्रभावित किया है। गुजरात टीम के साई सुदर्शन ने कुल 759 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता है। आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर उसका चयन इंग्लैंड जाने वाली टीम में भी हो गया है। पारी का आगाज करते हुए सुदर्शन ने कई अच्छी पारियां खेलीं। पंजाब किंग्स टीम के प्रियांश आर्य ने भी सबका ध्यान खींचा है। उसने भी अपनी टीम के लिए पारी की शुरूआत की। पंजाब के ही शशांक सिंह ने फिनिशर की भूमिका निभा कर कई उपयोगी पारियां खेलीं। श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी और शानदार बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया है। अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने का श्रेय उसे जाता है। हालांकि, दुर्भाग्य से श्रेयस को इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं चुना गया। चेन्नई टीम के 17 वर्षीय ओपनर आयुष म्हात्रे ने कप्तान धोनी को प्रभावित किया। इन युवाओं ने भविष्य के लिए उम्मीद जगाई है।

बेरंग दिखे कई दिग्गज खिलाड़ी

आईपीएल-2025 में कुछ खिलाड़ियों ने बहुत निराश किया। इनमें सबसे आगे लखनऊ टीम के कप्तान ऋषभ पंत का नाम है। फ्रैंचाइजी कंपनी ने उन्हें सबसे महंगे दाम 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने अपने आखिरी मैच में बेंगलुरू के विरुद्ध शतक जरूर लगाया लेकिन अपनी टीम को प्ले ऑफ तक नहीं पहुंचा सके। इस आईपीएल में पंत बिल्कुल नहीं चले। उनकी कप्तानी भी बेदम रही। इसी तरह कोलकाता टीम के वेंकटेश को काफी मोटी रकम 23.75 करोड़ मिली लेकिन रन बनाने में नाकाम रहे। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन 18 करोड़ में खरीदे गए थे पर, वह चोट से जूझते रहे। जिन मैचों में खेले उसमें रन नहीं बना पाए। चेन्नई टीम के कप्तान ऋतुराज भी 18 करोड़ में खरीदे गए थे लेकिन असर नहीं दिखा पाए। टूर्नामेंट के बीच में ही वह चोटिल होकर बाहर हो गए। कोलकाता टीम के रिंकू सिंह को 13 करोड़ मिले मगर, वह अपना जलवा नहीं दिखा सके।

गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने छोड़ी छाप

भारतीय टीम की ओर से कुछ मैच खेल चुके प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल में सर्वाधिक 25 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता है। गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए कृष्णा ने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। इसी कारण उसका चयन इंग्लैंड दौरे के लिए हो गया है। मोहम्मद शमी की गैर हाजिरी में इंग्लैंड में अच्छे प्रदर्शन का दबाव कृष्णा पर रहेगा। वह भारतीय टीम में स्थायी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंग्लैंड दौरा उनके लिए सुनहरा मौका है। जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस को प्ले ऑफ में अवश्य पहुंचाया लेकिन निर्णायक मैच में उनकी गेंदबाजी प्रभावहीन रही। पंजाब के खिलाफ 4 ओवर में बुमराह ने 40 रन दे दिए और कोई विकेट भी नहीं चटका सके। दरअसल, बुमराह फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं। शुरू के कई मैच में वह उतरे भी नहीं। फिटनेस की संदिग्ध दशा के नाते ही उन्हें इंग्लैंड दौरे पर कप्तान नहीं बनाया गया है।

HET

Once You
Buy The

Solar

The Power is Free

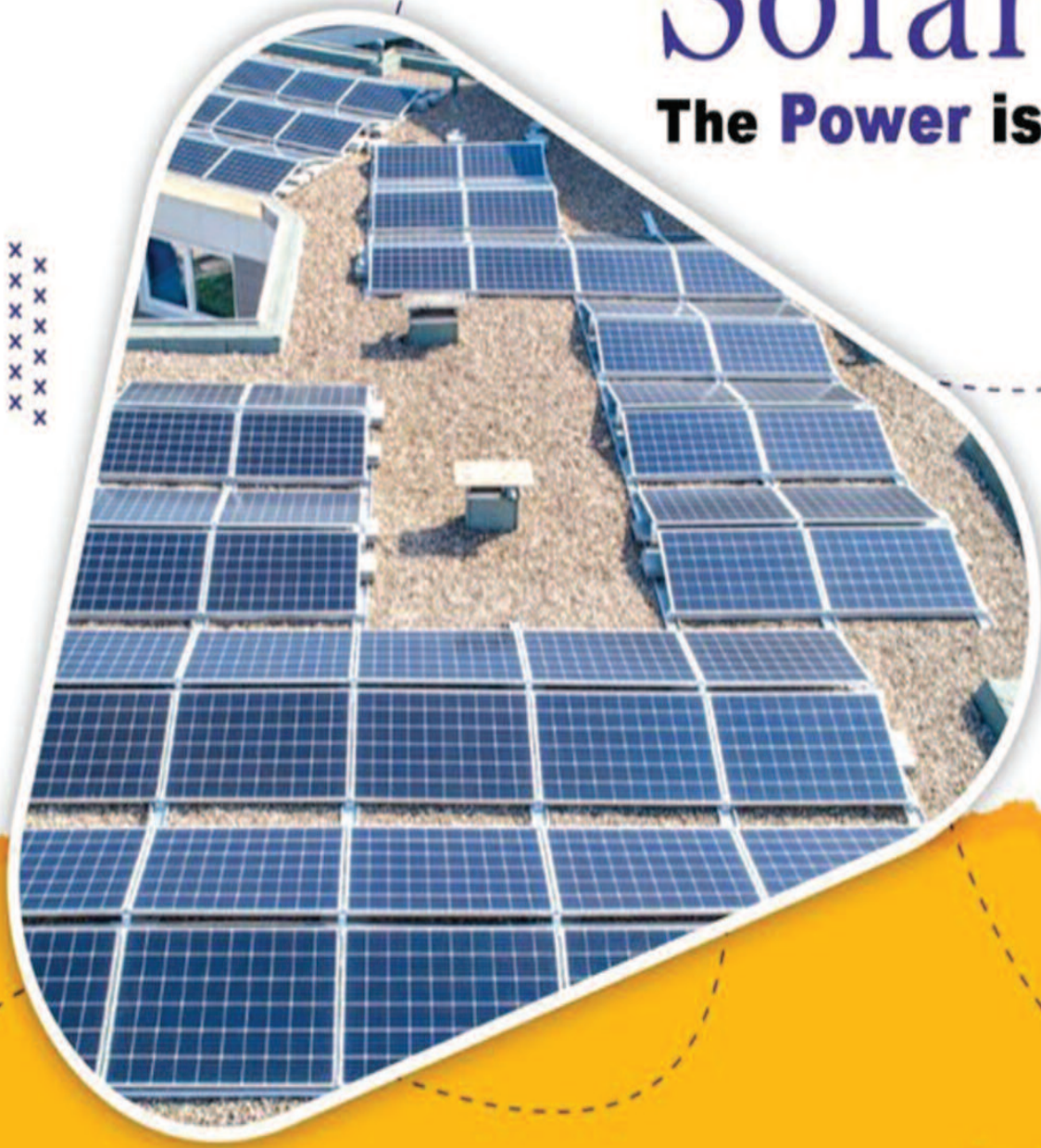

Harshita Electro & Telecom Pvt. Ltd.

SOLAR ON-GRID ROOFTOP SOLUTIONS | OFF GRID SOLAR SYSTEM
HYBRID SOLAR SYSTEM

Office : GF-135, Durga Tower, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad.
Phone : 9891116568, 9891116569, 9899562233

NABCB
QMS 008
AN ISO 9001 -2000 COMPANY

IS:8931

CM/L-3228449

supreme
luxury bathing

Assuring Excellence in Bath Faucets

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

अन्नदाता को नमन

किसान कल्याण मिशन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से

2.86 करोड़+ किसानों को

₹80,000 करोड़ हस्तांतरित

₹36,359 करोड़ से

94 लाख+

किसानों का ऋण मोचन

खुशहाल किसान

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 25 लाख+ कृषकों के 20 हेक्टेयर+ कृषि क्षेत्र का बीमा
- पी.एम. कुसुम योजना : किसानों को 75,000+ सोलर पंपों का आवंटन
- 49 जनपदों के 85,710 हेक्टेयर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम
- कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना
- गन्ना किसानों को रिकॉर्ड ₹2,73,000 करोड़+ गन्ना मूल्य का भुगतान
- चांगीपुर (बिजनौर), पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुंडेरवा (बस्ती) में नई चीनी मील की स्थापना
- 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन, 36 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण
- गन्ना मूल्य : ₹315 से बढ़कर ₹370 प्रति कुंतल, 1,10,600 टीसीडी अतिरिक्त पेराई क्षमता
- खाद्यान्न उत्पादन 669 लाख मीट्रिक टन/वर्ष तथा फल एवं सब्जी 400 लाख टन/वर्ष
- निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु 7,713 आश्रय स्थलों में 12.50 लाख गोवंश संरक्षित
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना : 2.60 लाख किसानों को कार्ड वितरण
- 976 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, 48.32 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि
- केन-बेतवा लिंक परियोजना की स्थापना हेतु ₹5,122 करोड़ का प्रावधान

काम दमदार - डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP